



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 2000/फाल्गुन 12, 1921

No. 36]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 2000/PHALGUNA 12, 1921

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2000

सं. एफ. 15(8)-बी(डी)/99.—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है :—

बजट 2000-2001

वित्त मंत्री

श्री यशवन्त सिन्हा

का

भाषण

29 फरवरी, 2000

महोदय,

मैं आपके सामने इस सहस्राब्दी का पहला बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

2. मैं यह बताना चाहूँगा कि वर्ष 2000-2001 का यह बजट कई मायनों में पहला है। यह नई सरकार का पहला बजट है जिसने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी एवं कुशल नेतृत्व में अक्टूबर, 1999 में कार्यभार संभाला था। यह हमारे गणतंत्र की दूसरी अर्द्ध-शती का पहला बजट और नई शताब्दी का भी पहला बजट है। समय के साथ मुझे आशा है कि इसमें अनेक रूप में पहला होने के विशेषण जुड़ जाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यह ऐतिहासिक उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है जिसका मैं विनम्रता से निर्वहन करता हूँ।

3. वर्ष 1999-2000 अनेक चुनौतियों का वर्ष रहा है, जैसे कश्मीर में 50-दिवसीय युद्ध, उड़ीसा में महाचक्रवात, आम चुनावों से पहले अनेक महीनों की राजनैतिक अनिश्चितता, कुछ कमजोर मानसून, विश्व में तेल की कीमतों का लगभग तिगुना हो जाना और विश्व आर्थिक सुधार की निरन्तर कमजोर स्थिति। फिर भी हमने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया है, अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अधिक मजबूत हुआ है।

4. आर्थिक निष्पादन का विस्तृत उल्लेख सदन के सामने मेरे द्वारा कल प्रस्तुत की गई आर्थिक समीक्षा में किया गया है। मैं इसमें से कुछ ही बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। एक व्यापक आधार वाला औद्योगिक सुधार चल रहा है। प्रतिकूल मौसम के कारण कृषि की कम वृद्धि के बावजूद इस वर्ष समग्र आर्थिक विकास लगभग 6 प्रतिशत होने की आशा है। आधारभूत सुविधा क्षेत्रक का निष्पादन बेहतर स्थिति में चल रहा है। पिछले 17 वर्षों में पहली बार मुद्रास्फीति की दर लगातार 42 सप्ताह तक 4 प्रतिशत से नीचे रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार) ने नवम्बर, 1999 में पिछले नवम्बर की तुलना में शून्य वृद्धि प्रदर्शित की है। हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए यह एक बहुत बड़ा वरदान है। सार्वजनिक खाद्य भण्डार रिकार्ड स्तर पर है। निर्यातों के मामले में भारी उलट-फेर हुआ है जिसमें पिछले वर्ष की ऋणात्मक वृद्धि की तुलना में डालर के संदर्भ में अप्रैल-दिसम्बर, 1999 में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारे साप्टवेयर निर्यातों में भी तेजी आ रही है। यद्यपि तेजी से बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों ने हमारे तेल आयात का बिल 6 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक बढ़ा दिया है फिर भी हमारे विदेशी मुद्रा रिजर्व ने नए कीर्तिमान प्राप्त किए हैं। निवेशकों के विश्वास की वापरी से हमारे शेयर बाजारों ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ है।

5. अपने पिछले दो बजटों में मैंने हमारी नीतियों की चलती आ रही कमियों को दूर किया है और हमारी कंपनियों को विश्व के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए स्वतंत्र बनाया है। हमने अपने कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ता प्रदान की है, अपने वित्तीय बाजारों को सशक्त बनाया है और एक जीवंत नई अर्थव्यवस्था की आधारशिला रखी है। इसके साथ मैं अपने तीसरे बजट में भारत को 7 से 8 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर से एक निरन्तर, समान एवं रोजगार-सृजनकारी दिशा में बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं ताकि एक दशक के अंदर हमारी धरती से गरीबी का संकट दूर हो सके। अगले दस वर्ष भारत के विकास के वर्ष होंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारी कार्ययोजना में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए:

- हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषकर कृषि एवं संबंधित क्रियाकलापों के विकास की बुनियाद को सुदृढ़ करना।
- इन्फोटेक, बायो-टेक्नालॉजी और फार्मास्युटिकल्स जैसे नए ज्ञान पर आधारित उद्योगों की क्रान्तिकारी क्षमता को विकसित करना।
- वस्त्र उद्योग, चमड़ा और कृषि प्रसंरकरण जैसे पारम्परिक उद्योगों और लघु उद्योग क्षेत्रक को सशक्त एवं आधुनिक बनाना।
- विद्युत, सड़क, पत्तन, दूरसंचार, रेलवे और विमान सेवा में आधारभूत सुविधा की अड़चनों को निरन्तर-दूर करना।
- समाज के सबसे गरीब एवं कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सामाजिक सेवाओं में कार्यक्रमों और नीतियों के द्वारा मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना।
- निर्यातों के त्वरित विकास, अधिक विदेशी निवेश और विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंधन के द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी भूमिका को सशक्त बनाना।
- वित्तीय अनुशासन की एक विश्वसनीय संरचना स्थापित करना जिसके बिना हमारी कार्ययोजना के अन्य घटक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

6. इन सभी क्षेत्रों में हमारे लोगों की सृजनात्मक शक्तियों को उभारने के लिए हमें सतत आर्थिक सुधार करते रहने चाहिए और इस प्रकार उत्पादकता वृद्धि के लाभ प्राप्त करने चाहिए। परन्तु हमारे सुधार सदाशयता और न्याय से निर्देशित होने चाहिए। माननीय राष्ट्रपति ने अक्तूबर,

1999 में संसद में अपने अभिभाषण के दौरान दूसरी पीढ़ी के सुधारों के हमारे कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा का उल्लेख किया है। हमारा यह बजट कार्यान्वयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है।

राजकोषीय प्रबंधन

7. आज हमें कमजोर करने वाली राजकोषीय स्थिति से उत्पन्न बड़ी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए और इस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। लम्बे समय से चलते आ रहे अत्यधिक राजकोषीय घाटों ने हमें भारी सरकारी ऋण और ब्याज अदायगी के निरंतर बढ़ते हुए बिल को विरासत में दिया है। इस वर्ष हमने राष्ट्रीय रक्षा, चुनावों और उड़ीसा के महाचक्रवात पर अप्रत्याशित व्यय किए हैं। पांचवें वेतन आयोग की बची हुई देनदारियों और राज्यों को विशेष राजकोषीय सहायता ने हमारा बोझ बढ़ा दिया है। इन सभी ने विनिवेश तथा राजस्व से प्राप्तियों में कमी के साथ हमारी निवल ऋण लेने की आवश्यकता (हमारा राजकोषीय घाटा) 1,00,000 करोड़ रुपए (एक लाख करोड़ रुपए) से आगे पहुंचा दी है। अगले वर्ष हमारे ब्याज बिल की लगभग 10,000 करोड़ रुपए (दस हजार करोड़ रुपए) की धनराशि भी इसमें बढ़ जाएगी। हमें रक्षा, योजना और ग्यारहवें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के अधीन राज्यों को अतिरिक्त हस्तान्तरणों के लिए अतिरिक्त संसाधनों को भी प्राप्त करना है। यदि हम संसाधन नहीं बढ़ाते हैं और इसके बजाय अगले वर्ष और अधिक ऋणों का सहारा लेते हैं तो विकास की हमारी संभावनाएं खतरे में पड़ जाएंगी, मुद्रारक्षीति का संकट पुनः सक्रिय हो जाएगा, दूसरे भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हो जाएगा और अगली पीढ़ी पर अनुचित बोझ पड़ जाएगा।

8. हमें अपनी राजकोषीय स्थिति व्यवस्थित रखनी चाहिए। इसका अर्थ है, कठिन निर्णय और बलिदान। इसके साथ-साथ हमारी अर्थव्यवस्था की अन्तर्निहित गतिशीलता की भी हमें रक्षा करनी चाहिए। केवल इसी के आधार पर सामाजिक न्याय के साथ निरन्तर विकास किया जा सकता है। इसी कारण से, गंभीर राजकोषीय कठिनाइयों के बावजूद योजना के लिए बजट सहायता वर्ष 1999-2000 (बजट अनुमान) में 77,000 करोड़ रुपए की तुलना में 11,100 करोड़ रुपए बढ़ाकर 88,100 करोड़ रुपए की जा रही है।

9. इसी तरह रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हमारी सेनाओं ने 'आपरेशन विजय' में पुनः एक बार फिर से यह प्रदर्शित कर दिया है कि विश्व में वह किसी से कम नहीं है। सरकार हमारे सैन्य बलों के आधुनिकीकरण और हमारी रक्षा तैयारियों की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रति बचनबद्ध है। मैंने इस बजट में रक्षा के लिए 58,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो इस वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 13,000 करोड़ रुपए अधिक है। अभी तक किसी अकेले एक वर्ष में रक्षा बजट को इतना अधिक नहीं बढ़ाया गया है। जब भी आवश्यकता होगी इसे और बढ़ाया जाएगा। अपनी प्रिय मातृभूमि की एक-एक इंच जमीन की सुरक्षा के लिए हम कुर्बानी देने से पीछे नहीं रहेंगे।

10. गत समय में केन्द्रीय सरकार के व्यय की संरचना अत्यधिक दुरुह और अनायास पूर्व-बढ़ोत्तरी वाली बन गई है। वार्षिक बजट परिव्ययों का आधे से अधिक हिस्सा हस्तान्तरण भुगतानों, ब्याज भुगतानों, रक्षा, आंतरिक सुरक्षा का है। रक्षा, बड़ी सब्सिडी, वेतन, भत्ते, एवं पेंशन और राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान आयोजना-भिन्न व्यय के लगभग 95 प्रतिशत और कुल व्यय के लगभग 70 प्रतिशत हैं। व्यय की स्वतः वृद्धि को रोकने और हमारे व्यय में संरचनात्मक

परिवर्तन लाने के लिए मैं निम्नलिखित पहल शुरू कर रहा हूँ:-

- सभी चालू स्कीमों (आयोजना एवं आयोजना-भिन्न) को पूर्ण शून्य आधार बजटीय संवीक्षा के अधीन रखा जाएगा। मैंने इस पहल की पिछले वर्ष घोषणा की थी और मुझे खुशी है कि यह कार्य 8 विभागों में पूरा कर लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप 69 स्कीमें बंद की जानी हैं या दूसरी स्कीम के साथ मिलाई जानी हैं। शेष विभागों में यह प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।
- पदों के सृजन के मानदंडों की पुनरीक्षा के द्वारा सरकारी विभागों की जनशक्ति की आवश्यकताओं का पुनः आकलन किया जाएगा।
- सरकारी विभागों और संस्थानों में नई भर्ती को न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक सीमित रखा जाएगा।
- अतिरिक्त स्टाफ की पुनः तैनाती की स्कीम को अधिक कारबाह बनाया जाएगा और उनके पुनः प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरप्लस पूल में रखे गए स्टाफ के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम भी शुरू की जाएगी।
- जहां कहीं संभव हो, लागत आधारित उपभोक्ता शुल्क लगाने की दृष्टि से सभी सब्सिडी की पुनरीक्षा की जाएगी।
- मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बिना किसी नई स्वायत्तशासी संस्थाओं का सृजन नहीं किया जाएगा। स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए बजटीय सहायता की पुनरीक्षा की जाएगी और उन्हें आंतरिक संसाधनों को अधिक से अधिक उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- समग्र ब्याज दर संरचना के साथ तालमेल बिठाने के उद्देश्य से सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर 1.4.2000 से 1 प्रतिशत कम करके 11 प्रतिशत की जा रही है।
- वर्तमान व्यय के वित्त पोषण के लिए अत्यधिक घरेलू ऋणों के कारण ऋण अदायगी संबंधी भुगतान अव्यवस्थित स्तरों तक पहुंच रहे हैं। इस खाते में व्यय को कम करने के लिए इस विनिवेश आय का एक हिस्सा वापरी योग्य सरकारी ऋण के लिए निर्धारित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए (एक हजार करोड़ रुपए) का आरंभिक प्रावधान किया गया है।

बड़ी सब्सिडियों के बारे में मुझे बाद में काफी कुछ कहना है।

11. ये उपाय आवश्यक हैं और इनकी केवल एक शुरूआत है। हम सरकार का आकार छोटा करने के उद्देश्य के लिए दृढ़-निश्चय के साथ कार्रवाई करेंगे और इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। परन्तु राजकोषीय घाटे की मध्यावधिक व्यवस्था के लिए हमें राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम में निहित मजबूत सांस्थानिक कार्यतंत्र की सहायता की भी आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रशासन की कार्यसूची में इसका सुझाव दिया गया था। इस मुद्दे की जांच करने और उचित सिफारिशें देने के लिए मैंने एक समिति का गठन कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि इस वर्ष के दौरान आवश्यक कानून प्रस्ताव मैं सदन के सामने लाऊंगा।

12. राजकोषीय प्रबंधन की चुनौती केन्द्र सरकार तक ही सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में तेजी से गिरावट आई है। राजस्व घाटे बढ़ गए हैं और राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए ऋणों का अधिक सहारा लिया जा रहा है। राज्य स्तर पर राजकोषीय सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। जहां राज्य सरकारों की हमने हर तरह से सहायता की है वहां इन मुद्दों से निपटने के लिए कुछ राज्यों द्वारा प्रदर्शित कृत-संकल्पता ने अत्यधिक सहायता भी की है। राज्यों में राजकोषीय सुधारों को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष और अधिक सामूहिक उपाय करने हेतु मैं प्रयत्न करूंगा। ग्यारहवें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट इस संबंध में नीतिगत कदम उठाने के लिए बहुमूल्य सामग्री प्रदान करेगी।

कृषि एवं ग्रामीण विकास

13. मेरा दृढ़ विश्वास है कि गरीबी उन्मूलन, आय एवं रोजगार उत्पन्न करने, खाद्य-सुरक्षा सुनिश्चित करने और उद्योगों एवं सेवाओं के लिए भरपूर धरेलू बाजार बनाए रखने हेतु कृषि का निरंतर एवं व्यापक आधार पर विकास अनिवार्य है।

14. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमें सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सांस्थानिक माध्यमों से कृषि के लिए इस वर्ष ऋण प्राप्ति लगभग 41,800 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वर्ष 2000-2001 में इसके 20 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 51,500 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचने की आशा है। पिछले दो बजटों में हमने ग्रामीण ऋण प्राप्तियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय आरंभ किए थे। इस बजट में पहले के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने और आगे नए उपाय करने का मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

- नाबार्ड द्वारा प्रबंधित ग्रामीण आधार-सुविधा विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) ग्रामीण आधार-सुविधा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एक लोकप्रिय एवं प्रभावी रकीम के रूप में उभरी है। पिछले वर्ष मैंने आर.आई.डी.एफ.V के लिए बैंकिंग क्षेत्रक से 3,500 करोड़ रुपए के बढ़े हुए आवंटन की घोषणा की थी और ऋणों की अदायगी की अवधि बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी थी। आर.आई.डी.एफ. के दायरे का भी विस्तार किया गया था ताकि ग्राम स्तरीय आधारभूत सुविधाओं की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों, स्व-सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य पात्र संगठनों को ऋण दिया जा सके। इस वर्ष आर.आई.डी.एफ.VI की निधि को बढ़ाकर 4,500 करोड़ रुपए किया जाएगा और इसके द्वारा दिए गए ऋणों पर प्रभारित ब्याज आधा प्रतिशत कम किया जाएगा।
- अधिकांश देशों में सूक्ष्म वित्तीय व्यवस्था गरीबी उन्मूलन हेतु एक प्रभावी माध्यम के रूप में सामने आयी है। अपने पिछले बजट में, मैंने नाबार्ड तथा सिडबी से कहा था कि वे सूक्ष्म उद्यमों के विकास हेतु 50,000 स्व-सहायता समूहों को इसमें शामिल करें। स्वयं नाबार्ड द्वारा चालू वर्ष के दौरान ऐसे 50,000 समूहों को बैंकों के साथ सम्बद्ध करने की सम्भावना है। नाबार्ड और सिडबी वर्ष 2000-2001 के दौरान अतिरिक्त एक लाख समूहों को इसमें शामिल करेंगे। इस कार्यक्रम में और अधिक तेजी लाने के लिए नाबार्ड में एक सूक्ष्म वित्त विकास निधि का निर्माण किया जाएगा जिसमें भारतीय

रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंकों और अन्यों से प्रारम्भिक अंशदान 100 करोड़ रुपए (सौ करोड़ रुपए) होगा। यह विकास निधि सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को आरम्भिक निधि उपलब्ध कराएगी तथा प्रशिक्षण और व्यवस्था प्रबन्धन तथा आंकड़े तैयार करने में अवसर्सचनात्मक सहयोग प्रदान करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों सहित कमजोर वर्गों द्वारा स्थापित सूक्ष्म उद्यमों के संवर्धन पर विशेष जोर दिया जाएगा।

- ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने की सहकारी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तथापि, मुख्यतया अत्यधिक नौकरशाही तथा राज्य सरकारों और नाबार्ड के अतिव्याप्ति क्षेत्राधिकार की वजह से पिछले कुछ समय से समरयां उत्पन्न हो गयी हैं। कुछ राज्य सरकारों ने सहकारी संस्थाओं को यथार्थ रूप से प्रोत्साहन देने के लिए पहले ही कानून बनाने सम्बन्धी कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है। ग्रामीण ऋण के लिए, बैंकिंग मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड की पर्यवेक्षण भूमिका की रूपांतरण रूपरेखा तैयार करना भी आवश्यक है। अधिक गतिशील ग्रामीण सहकारी ऋण व्यवस्था हेतु इन दो पूर्व अपेक्षाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मैं नाबार्ड में एक निधि की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं। इसके बाहर सरकार द्वारा पूर्व गठित कपूर समिति की आगामी सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में तैयार किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक इस बीच बैंकों को यह सलाह दे रहा है कि वे उन सहकारिताओं की ऋण आवश्यकता को प्राथमिकता दें जो पूर्णतः उपभोक्ता सदस्यों द्वारा नियंत्रित हैं तथा जिनका प्रबन्धन उनके द्वारा विवेकसम्मत तरीके से किया जा रहा है।
- किसान, क्रेडिट कार्ड सम्बन्धी कार्यक्रम भी उत्तरोत्तर-आगे बढ़ रहा है। सहकारी बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों ने अभी तक मिलकर-कृषकों के लिए 50 लाख से अधिक कार्ड तथा कार्ड एवं पास बुक जारी किए हैं। मैं नाबार्ड तथा वाणिज्यिक बैंकों से कह रहा हूं कि वह अपने प्रोत्साहन सम्बन्धी प्रयासों को दुगुना करें ताकि मार्च, 2001 तक 75 लाख अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकें।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः पूंजीकरण सम्बन्धी हमारे प्रयासों के कारण 158 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रचालन मुनाफे दिखा रहे हैं। इनमें से 48 क्षेत्रीय बैंक अपने संचित घाटों को समाप्त करने में सफल हुए हैं। ग्रामीण वित्त-पोषण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के महत्व को देखते हुए इनको सुदृढ़ करने के इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

15. योजना आयोग एवं कृषि मंत्रालय ने कृषि की 28 चालू अलग-अलग केन्द्र प्रायोजित रक्कीमों को एक व्यापक कार्यक्रम में एकीकृत करने की कार्यप्रणाली तैयार कर ली है। इससे द्विरावृत्ति दूर होगी, समर्थनकारी कार्यक्रम की उत्पादकता बढ़ेगी और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर क्रियाकलापों को विकसित करने एवं चलाने के लिए राज्य सरकारों को अधिक सुविधा मिलेगी। अभिमुखता एवं गणतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के उद्देश्यों, जिनका मैंने अपने पूर्व बजटों में उल्लेख किया था, की दिशा में बढ़ने का यह एक बड़ा कदम है।

16. देश में भूमि उपयोग के स्वरूप, विभिन्न क्षेत्रों में कृषि जलवायु दशाओं के सम्बन्ध में कृषि के विकास और अपने वन संसाधनों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर हमें

अपनी दीर्घकालिक नीति की समीक्षा तथा समन्वय करने की अत्यन्त आवश्यकता है। हमें वन सम्पदा के संरक्षण तथा विकास, ऊसर भूमि का इष्टतम उपयोग, जलसंभर विकास, जैव विविधता का बचाव आदि कई सम्बन्धित विषयों पर एक समेकित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। निहित मुद्दों की जटिलता को देखते हुए भूमि उपयोग नीति पर एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाएगा जिसमें संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे और वह विभिन्न पहलुओं की जांच करेंगे तथा सरकार को उचित सिफारिशें प्रदान करेंगे।

17. हमारी सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये पूर्ण रूप से वचनबद्ध है कि आर्थिक सुधारों के फलों का आस्वादन समाज के सभी वर्गों के लोग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी और अधिक विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग कर सकें। सामाजिक एवं आर्थिक आधार भूत सुविधा के यह पांच तत्व जीवन की गुणवत्ता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये महत्वपूर्ण हैं अर्थात् स्वारक्ष्य, शिक्षा, पेयजल, आवास एवं सड़कें।

18. स्वतंत्रता प्राप्ति के 52 वर्षों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था बहुत असंतोषजनक बनी हुई है। हमारे चालीस प्रतिशत गांवों में उचित सड़कें नहीं हैं; 1.8 लाख गांवों में 1 किलोमीटर के भीतर कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, 4.5 लाख गांवों में पेयजल की समरया है, कुल अनुमान 140 लाख ग्रामीण रिहायशी आवासों की कमी दर्शाते हैं; ग्रामीण स्वारक्ष्य के आधारभूत ढांचे में काफी कमियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की इतनी अधिक कमी स्वीकार्य नहीं है और सरकार तेजी से उन्हें दूर करने के लिए वचनबद्ध है।

19. बुनियादी शिक्षा का सार्वभौमिकरण हमारे प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इन प्रयासों पर नए सिरे से बल देने और ध्यान केन्द्रित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन बुनियादी शिक्षा और साक्षरता का एक नया विभाग पहले ही सृजित किया जा चुका है। नई कुछ पहलों में "सर्व शिक्षा अभियान" नामक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की एक नई स्कीम शामिल है जो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात में बकाया जिलों को शामिल करने के लिये 2003 तक सभी बच्चों को दाखिल करने और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने में सहायक होगी। साक्षरता के क्षेत्र में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनःसशक्ति बनाया जाएगा ताकि वर्ष 2005 तक साक्षरता दर बढ़ाकर 75 प्रतिशत की जा सके। प्राथमिक शिक्षा के लिए अगले वर्ष में योजना आवंटन 2,931 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,729 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रयत्नों में तेजी लाने और इसमें लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की गति तेज करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में नया पेय जल आपूर्ति विभाग स्थापित किया गया है। हमारा उद्देश्य अगले पांच वर्षों में सभी ग्रामीण बस्तियों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अगले वर्ष में लगभग 60000 बस्तियों और 30000 विद्यालयों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। विभाग के लिए परिव्यय इस वर्ष 1,807 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,100 करोड़ रुपए किया जा रहा है। जनन एवं शिशु स्वारक्ष्य कार्यक्रम के लिए 1999-2000 में 695 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में 1,051 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। ग्रामीण आवास स्कीमों के लिए 1,710 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है।

20. इन प्रयत्नों में अधिक तेजी लाने के लिये मैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना' नामक एक नई स्कीम चलाने की घोषणा कर रहा हूं जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं

को पूरा करने के लिये समय-बद्ध कार्यक्रम चलाना है। मैं बजट में इस स्कीम के लिये 5,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान कर रहा हूँ। इस धनराशि में से 2,500 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़क निर्माण व ग्रामीण-संयोजन सुविधा सुधार को एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाने के लिये निर्धारित किये जायेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत इन क्षेत्रकों में विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय मार्ग निर्देश निर्धारित करेंगे और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानिटरिंग करेंगे। पूर्व बुनियादी न्यूनतम सेवा स्कीम को इस नई स्कीम में मिला दिया जाएगा। इस प्रकार ग्रामीण आबादी की पांच बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित स्कीमों के लिए बजट में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का समग्र प्रावधान है।

ग्रामीण आवास

21. सरकार के राष्ट्रीय एजेंडे में 'सभी के लिए आवास' को एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में चुना गया है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए देहाती इलाकों में 25 लाख आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समाज के विभिन्न तबकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कीमें तैयार की गई हैं:-

- (i) इन्दिरा आवास योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए 12 लाख से अधिक घरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन हेतु बजट में 1,501 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है।
- (ii) उन परिवारों के लिए जिनकी वार्षिक आय 32,000 रुपए प्रतिवर्ष से कम है, ग्रामीण ऋण और सब्सिडी स्कीम के तहत 1 लाख घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस स्कीम के लिए बजट में 92 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की जा रही है।
- (iii) ग्रामीण आवास बैंक स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण आवास वित्त स्कीम के तहत 1.5 लाख घरों के निर्माण के लिए बैंकों और आवास वित्त कम्पनियों को पुनर्वित उपलब्ध कराएगा।
- (iv) ग्रामीण क्षेत्रों में आवास वित्त की उपलब्धता में और सुधार लाने के लिए सरकार ने नौवीं योजना अवधि के दौरान 'हुड़को' को 350 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता मुहैया कराने का निर्णय किया है। इसमें से 200 करोड़ रुपए पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं और आगामी वर्ष में और 100 करोड़ रुपए की राशि रिलीज करने का प्रस्ताव है। इस बढ़ी हुई इक्विटी सहायता से हुड़को इन निधियों को बढ़ाने और आगामी वित्तीय वर्ष में ग्रामीण इलाकों में लगभग 9 लाख घरों के निर्माण के लिए वित्त को सुलभ और प्रदान करने हेतु और अधिक संसाधन जुटाने में समर्थ होगा।
- (v) सहकारी क्षेत्रक और स्वयंसेवी एजेन्सियां आदि और 1.5 लाख घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करेंगी।

गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा

22. एक तिहाई से अधिक आबादी अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही है। इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हमारे समाज के सबसे गरीब तबकों को थोड़ा बहुत सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान किया जाए। मैंने सामूहिक बीमा की एक नई स्कीम अर्थात्

‘जनश्री बीमा योजना’ शुरू करने का निर्णय किया है, जिसके तहत लाभार्थियों को स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में 20,000 रुपए, दुर्घटनावश मृत्यु अथवा सम्पूर्ण स्थाई विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपए और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थाई विकलांगता के लिए 25,000 रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। प्रीमियम की राशि जीवनांकिक आधार पर तय की जाएगी। गरीबी की रेखा से नीचे के इस स्कीम के सहभागी केवल आधे प्रीमियम की अदायगी करेंगे, शेष अंशदान जीवन बीमा निगम की विद्यमान सामाजिक सुरक्षा निधि, जिसमें सरकार ने उपयुक्त बढ़ोत्तरी की है, के अर्जनों में से किया जाएगा। इस आधार पर, लाभार्थी द्वारा अदा किए जाने वाला मासिक प्रीमियम 10 रुपए अथवा उससे कम होने की आशा है। यह स्कीम हमारे देश के निर्धनतम लोगों को बीमा कवर प्रदान करने की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करेगी।

महिलाओं की अधिकारिता

23. राष्ट्रीय संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक विकास की मुख्यधारा में उनका अधिकारपूर्ण स्थान सुनिश्चित करने की अत्यावश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका से संबंधित सभी मौजूदा विधान और सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के अधीन एक कार्य दल गठित करेगी। यह कार्य दल वर्ष 2001 को ‘महिला अधिकारिता वर्ष’ के रूप में मनाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने में हमारी सहायता करेगा।

जनसंख्या, स्वास्थ्य और पर्यावरण

24. सरकार ने हाल ही में एक नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की है जिसका उद्देश्य 2010 तक कुल गर्भधारण दरों को कम करके प्रनिर्स्थापित स्तरों तक लाना है। इस उद्देश्य को कार्यान्वयित करने के लिए परिवार कल्याण विभाग का आयोजना आबंटन बजट अनुमान 1999-2000 में 2,920 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष के लिए 3,520 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

25. हमारी स्वास्थ्य देखभाल में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की भूमिका को समझते हुए विभाग के लिए योजना आबंटन दुगुना किया जा रहा है। औषधियों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण और कालेजों, औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं एवं विनिर्माणों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाएगा। इससे औषधि विनिर्माण के क्षेत्र में निर्यातों में तेजी लाने में भी मदद मिलेगी।

26. भावी पीढ़ियों के लिए हमें अपने बनों एवं पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और उनका सम्पोषण करना चाहिए। तटीय क्षेत्रों के साथ कच्छ वनस्पति के पुनरुत्पादन तथा आश्रय स्थलों के निर्माण, के लिए बांस उगाने और वानिकी कार्यक्रम, औषधीय वनस्पतियों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निधियां उपलब्ध करायी जा रही हैं। ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर देने से हमारे समाज के सर्वाधिक निर्धन वर्गों के लाखों लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठेगा।

लघु उद्योग

27. लघु उद्योग क्षेत्रक औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यातों में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बढ़ते हुए घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा के संदर्भ में, हमारी कार्य

योजना है कि ऋण और प्रौद्योगिकी की संवर्धनात्मक नीतियों के जरिए इस क्षेत्रक को सहायता प्रदान की जाए। लघु उद्योग इकाइयों के लिए ऋणों की प्राप्ति में सुधार लाने हेतु मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

- ऋणाधार जमानत उपलब्ध कराने की आवश्यकता बहुत छोटी इकाईयों के लिए बैंक ऋण की प्राप्ति में एक प्रमुख अड़चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 1 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए ऋणाधार अपेक्षा को समाप्त करने के अनुदेश जारी किए हैं। लघु क्षेत्रक के लिए सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा रही है।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और बैंकों की मौजूदा संयुक्त ऋण रकीम एक एकल खिड़की के माध्यम से कार्यशील और सावधि ऋण मुहैया करा कर छोटे उधारकर्ताओं की मदद करती है। छोटे उधारकर्ताओं की ऋण उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त ऋण सीमा को 5 लाख रु. से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा रहा है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक जिला और जिले के भीतर लघु उद्योगों में कम से कम एक विशिष्ट लघु उद्योग बैंक शाखा कार्यरत हो, मैं सरकारी क्षेत्र के बैंकों से लघु उद्योग शाखाओं के उनके कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए कह रहा हूं। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, लघु उद्योग शाखाओं से आइ.एस.ओ. प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है।
- गत वर्ष, मैंने घोषणा की थी कि लघु उद्योगों के लिए एक ऋण गारंटी रकीम शुल्की की जाएगी। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इस प्रयोजन हेतु एक नई केन्द्रीय योजना को तैयार कर लिया गया है और बजट में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह रकीम सिडबी के मार्फत कार्यान्वयित की जाएगी और इसके अन्तर्गत बैंकिंग क्षेत्रक से 10 लाख रुपए तक के ऋण शामिल होंगे। गारंटीशुल्क ऋणों को प्रतिभूतियों का रूप दिया जाएगा और द्वितीयक ऋण बाजार में इनकी खरीद-फरोख्त की जा सकेगी।

28. सिडबी राष्ट्रीय इकिविटी निधि रकीम चलाता है जिसके तहत 15 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए इकिविटी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। लघु उद्योग उद्यमियों की और सहायता करने के लिए परियोजना सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी।

29. सिडबी इस समय लघु उद्योग इकाइयों के प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास आधुनिकीकरण निधि रकीम चला रहा है। इस रकीम में कुछ रियायती व्यवस्थाएं हैं जिनमें प्रत्यक्ष सहायता के लिए मूल उधार दर पर ब्याज और अप्रत्यक्ष वित्त के लिए मूल दर से 2 प्रतिशत कम पर पुनर्वित्त शामिल है। इस रकीम का प्रचालन और 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है।

30. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आइ.सी.) प्रति व्यक्ति कम निवेश के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करने के साधन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रक को बढ़ावा देना जारी रखेगी जिससे कि इसके

उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन सकें। विपणन प्रयासों में तेजी लाने के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने उत्पादों के लिए एक समान ब्रांड नाम शुरू करेगा और घरेलू तथा निर्यात विपणन के लिए व्यावसायिक रूप से प्रबंधित विपणन कम्पनी की स्थापना भी करेगा।

उद्योग और पूंजी बाजार

31. पिछली सहस्राब्दियों में भारत ने ज्ञान के बल पर विश्व को अपना अनुयायी बनाया था। आज इतिहास स्वयं को दुहरा रहा है। युवा भारतीय उद्यमी सूचना तकनीक क्रान्ति की अगुवाई कर रहे हैं चाहे वे सिलिकॉन वैली में हो, बंगलौर अथवा हैदराबाद में हों। उन्होंने हमें दिखा दिया है कि कैसे विचारों, ज्ञान, उद्यमशीलता और प्रौद्योगिकी के मेल से आय, रोजगार और समृद्धि में असाधारण तरक्की हासिल की जा सकती है। जो कम्पनियां 5 वर्ष पहले तक अज्ञात थीं, आज विश्व की अग्रणी कम्पनियां बन चुकी हैं। हमें ज्ञान आधारित उद्यम और रोजगार सृजन के विकास को बढ़ावा देने के लिए हरसम्बव प्रयास करना चाहिए।

32. भावी सफलता की एक प्रमुख जरूरत उद्यम पूंजी वित्त है। सम्पूर्ण समीक्षा के बाद मैं उद्यम पूंजी निधियों के लिए कर संव्यवहार में वृहत उदारीकरण का प्रस्ताव कर रहा हूं। मैं इसका ब्यौरा बाद में दूंगा। प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, 'सेबी' देशी और विदेशी उद्यम पूंजी निधियों दोनों के पंजीकरण और विनियमन के लिए एकल स्थानिक नोडल एजन्सी होगी। उद्यम गतिविधि डॉट-काम कम्पनियों तक सीमित नहीं है। विचार और उद्यमशीलता, जो उद्यम पूंजी के लिए आवश्यक हैं, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। कर कानूनों और सेबी के दिशा निर्देशों को तदनुसार निरुपित किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस उदारीकरण से सिलिकॉन वैली और अन्यत्र के अनिवासी भारतीयों को अपनी पूंजी, ज्ञान और उद्यम का उनकी मातृभूमि में स्थित उद्यमों में निवेश करने को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।

33. हाल के महीनों में भारत सहित समूचे विश्व भर में स्टॉक बाजारों में उछाल आया है। अनुभव ने हमें सिखाया है कि मुश्किल भरा समय भी आ सकता है, ऐसे कठिन समय में ही स्टॉक एक्सचेजों की निवेशक संरक्षण निधियां वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसी के संदर्भ में अपने भाषण के भाग 'ख' में इस पर कुछ प्रकाश डालूंगा।

34. हमारे विवेकसम्मत वृहत-आर्थिक प्रबन्धन और मुद्रा-परिवर्तनीयता के प्रति अनुसंशोधित नीति की बदौलत हमने गत दो वर्षों के पूर्वी एशियाई संकट का सामना सफलतापूर्वक किया है। लेकिन हमें एहतियात को बुजदिली नहीं समझना चाहिए। हमें भारतीय फर्मों और व्यापारिक मूल के घरानों को सुदृढ़ भारत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के रूप में विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए हमारी फर्मों को, विशेषकर विदेशों में व्यवसायों के अर्जन के लिए पूंजी खाता लेनदेनों का काम शुरू करने के लिए अधिकाधिक लघीलापन प्रदान करना आवश्यक है। पिछले महीने सरकार ने भारतीय कम्पनियों को सरकार के पूर्व अनुमोदनों के बिना ए.डी.आर./जी.डी.आर. के निर्गमों के माध्यम से निवेश हेतु निधियां जुटाने के लिए स्वीकृति देने की एक नीति की घोषणा की थी। इन प्राप्तियों की 50 प्रतिशत तक धनराशि का विदेशी बाजार में कम्पनियां खरीदने के लिए उनके द्वारा उपयोग किया जा सकता है। हमने 27 दिसम्बर, 1999 को स्वतः आधार पर 100 मिलियन अमरीकी डालर तक स्टॉक की अदला-बदली के विकल्पों के माध्यम से विदेशी बाजार में सॉफ्टवेयर कम्पनियों के अधिग्रहण की उदारीकृत व्यवस्था की घोषणा की थी। मेरी योजना विदेशों में कम्पनियों के अधिग्रहण सम्बन्धी नीति को

पुनः उदार बनाने की है ताकि भारतीय कम्पनियां ज्ञान आधारित क्षेत्रकों में और तेजी से आगे बढ़ सकें और भारतीय बहुराष्ट्रिक ऐसे क्षेत्रों में अपनी बुनियाद रख सकें जों आर्थिक रूप से हमारे लिये अधिक लाभकारी हों। अन्य क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए भी मैं भारतीय कम्पनियों के लिए स्वतः मार्ग के अन्तर्गत मौजूदा 15 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा को बढ़ाकर 50 मिलियन अमरीकी डालर करने का प्रस्ताव करता हूं तथा इससे आगे यह अधिग्रहण विदेशी निवेश समिति की रवीकृति से किया जाएगा।

35. पोर्टफोलियो निवेश के संबंध में विद्यमान नीति के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आइ.आइ.) को किसी कंपनी में इक्विटी शेयरों के कुल 24 प्रतिशत निवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसे निवेशक मंडल के अनुमोदन और कंपनी की साधारण सभा के एक विशेष प्रस्ताव द्वारा 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। हमारी सर्वोत्तम कंपनियों की विदेशी पोर्टफोलियो निवेश तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए मैं इस सीमा को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर रहा हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

36. हमारे ज्ञान-आधारित उद्योगों का सतत विकास अन्तर्गत हमारे समाज में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति और प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं प्रसार पर निर्भर करेगा। हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपनी क्षमता का उपयोग प्रधानमंत्री द्वारा पिछले माह भारतीय विज्ञान सम्मेलन के अवसर पर अपने सम्बोधन में परिकल्पित आधुनिक भारत के स्वप्न को साकार करने में करना चाहिए। प्रासंगिक प्रौद्योगिकी दृष्टि-परियोजनाओं को शुरू करने और हमारे विश्वविद्यालयों और अनुसंधान व विकास संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के बजट में 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान कर रहा हूं। एक नई सहरत्राद्वि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व अभिक्रम शुरू करने के लिए मैं विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान के विभाग के बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर रहा हूं। यह उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करेगा जो राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करते हैं और यह सरकार और निजी क्षेत्रक के बीच भागीदारी पर आधारित होगा।

37. नई बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की व्यवस्था का पूरी तरह लाभ उठाने के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों और अनुसंधान व विकास संस्थाओं को उनके पेटेन्ट कराने के प्रयासों को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सरकार ने विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को सार्वजनिक रूप से निधिपोषित अनुसंधान के माध्यम से बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से प्राप्त राजस्व को रखे रहने और अन्वेषक के साथ राजस्व के एक हिस्से में भागीदारी करने की भी अनुमति दी है।

38. पेटेन्ट कार्यालय और ट्रेड मार्क रजिस्टर के आधुनिकीकरण का कार्य काफी लम्बे समय से प्रतीक्षित है। सरकार ने पेटेन्ट कार्यालय के लिए 75 करोड़ रुपए की आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी दी है और हमारा प्रयास रहेगा कि इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन की दिशा में सभी अड्डचनों को दूर किया जाए।

बैंकिंग और वित्त

39. हाल के पूर्वी एशियाई संकट ने बैंकिंग क्षेत्रक को सुदृढ़ करने के लिए सुधार लागू

करने के अत्यधिक महत्व को प्रदर्शित किया है। हाल के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों के लिए आम तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुरूप विवेकपूर्ण मानदण्ड निर्धारित करता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों को पूरा करने और बैंकों को उनकी गतिविधियों में विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। सरकारी बजट के अत्यधिक तंगी में होने की वजह से, यह पूंजी जनता से जुटाई जानी होगी जिसका परिणाम सरकारी शेयरधारिता में कटौती के रूप में होगा। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की न्यूनतम शेयरधारिता को कम करके 33 प्रतिशत करने के लिए नरसिम्हन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय किया है। ऐसा बैंकों के सरकारी क्षेत्रक स्वरूप में परिवर्तन किए बिना और यह सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा कि शेयरों के नये निर्गम को जनता द्वारा व्यापक रूप से सफल बनाया जाए। समिति ने यह विचार भी व्यक्त किया था कि बैंकों के बोर्डों को कॉरपोरेट रणनीति और व्यवसाय प्रबन्धन के सभी पहलुओं पर निर्णय लेने की पर्याप्त स्वायत्तता होनी चाहिए और यह शेयरधारकों अर्थात शेयरधारकों, कर्मचारियों और मुख्य रूप से जनता के प्रति जबावदेह होने चाहिए। विशेष रूप से, राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के हितों का पूरी तरह संरक्षण किया जाएगा। यह प्रस्ताव है कि बैंकों के बोर्डों को आवश्यक लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विधायी उपबन्धों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं।

40. जैसा कि माननीय सदस्यगण अवगत हैं, सरकारी क्षेत्रक के कमजोर बैंकों के पुनर्गठन सम्बन्धी कार्य दल ने एक वित्तीय पुनर्गठन प्राधिकरण (एफ.आर.ए) के गठन का सुझाव दिया था। यह निर्णय किया गया है कि एफ आर ए का एक संशोधित रूप तैयार किया जाए। अतः किसी भी बैंक के सम्बन्ध में, जिसे कमजोर या सम्भाव्य रूप से कमजोर समझा जाता है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शासित करने वाली संविधियों में संशोधन किया जाएगा जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों के आधार पर निदेशक मण्डल को बरखास्त करने और ऐसे बैंक के लिए विशेषज्ञों और व्यावसायिकों को मिलाकर एक एफ आर ए के गठन की व्यवस्था की जा सके। इन संशोधनों से एफ आर ए बैंक के बोर्ड के सभी अधिकारों सहित विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा।

41. सरकार किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक को बन्द नहीं करेगी। बैंकों के एक जिम्मेदार स्वामी की हैसियत से सरकार ने निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए कमजोर बैंकों के पुनर्पूर्जीकरण पर विचार करने का निर्णय किया है, बशर्ते कि सम्बन्धित बैंकों द्वारा स्वामी के रूप में सरकार को और विनियामक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को स्वीकार्य एक व्यवहार्य पुनर्गठन कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाए।

42. हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंकों में गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों (एनपीए) का उच्च स्तर निरन्तर चिन्ता का विषय बना हुआ है। बैंक प्राप्तों की वसूली के लिए सक्षम और प्रभावी तंत्र एनपीए को कम करने के लिए निर्णायक रूप से महत्वपूर्ण है। मुझे इस सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि एक अध्यादेश जारी करके बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली, अधिनियम 1993 में व्यापक संशोधन किए गए हैं। पांच और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डी.आर.टी.) और चार और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की रथापना की गई है अथवा वे स्थापना के अन्तिम चरण में हैं। मैं मुम्बई में चार और डी.आर.टी. और कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई में

एक-एक और डी.आर.टी. की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं जिससे कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देयताओं के शीघ्र न्यायनिर्णयन और वसूली को सुविधापूर्ण बनाया जा सके।

43. नई गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्ति की वृद्धि को, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के मध्य उधारकर्ताओं और सम्भावित उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान के लिए बेहतर संस्थागत तंत्रों के जरिए भी रोका जा सकता है। एक ऋण सूचना व्यूरो की स्थापना के तौर तरीकों की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यकारी दल ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट-प्रस्तुत की है। इसकी सिफारिशों के आधार पर शीघ्र ही एक ऋण सूचना व्यूरो की स्थापना की जाएगी।

44. आधुनिक वित्त की तेजी से बदलती दुनियां में मौद्रिक नीति के संचालन और वित्तीय प्रणाली के विनियमन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक प्रचालनात्मक लचीलापन प्रदान करना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, मैं संगत मौजूदा विधानों को संशोधित करने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने का इरादा रखता हूं।

45. इसी प्रकार, सरकारी ऋण बाजार का विकास सुविधाजनक बनाने के लिए विधायी ढांचे को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, जिसे मैं पुराने लोक ऋण अधिनियम, 1944 को प्रतिस्थापित करके लाने का प्रस्ताव रखता हूं के माध्यम से सुदृढ़ और आधुनिकीकृत करने की आवश्यकता है।

46. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक एकमात्र कलकत्ता-स्थित विकास वित्तीय संस्था है। इसे अपना कारोबार विविधीकृत और विस्तारित करके अपनी व्यवहार्यता और लाभदायकता में सुधार करने योग्य बनाने के लिए सरकार कंपनी की तरजीही-पूँजी में अभिदान करेगी।

47. एन.बी.एफ.सी. वित्तीय माध्यरथ के रूप में और उद्योग तथा सेवाओं के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले 3 वर्षों से भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि केवल वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुचालित एन.बी.एफ.सी. को ही लोक जमा स्वीकार करने की अनुमति दी जाय, इस क्षेत्र के विनियमन को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं। मैं एक नया विधेयक लाने का प्रस्ताव रखता हूं, जो एन.बी.एफ.सी. के दोषपूर्ण अथवा घोखाधड़ीपूर्ण कार्रवाईयों की स्थिति में जमाकर्ताओं का हाथ मजबूत करेगा।

आधारभूत सुविधायें

48. हमारी अर्थव्यवस्था के तीव्र और सतत विकास में आधारभूत सेवाएं मुख्य अङ्गचन बनी हुई हैं। हमने निजी सेवा प्रदानकर्ताओं को प्रोत्साहित करने और अधिकांश आधारभूत सुविधा क्षेत्रों में स्वतंत्र विनियामक संरचना स्थापित करने में काफी प्रगति की है। हमने इन क्षेत्रों में मौजूदा सरकारी संगठनों को अधिक प्रचालनात्मक और वाणिज्यिक स्वायत्तता प्रदान करने की भी मांग की है। हम आगामी वर्ष के दौरान दूरसंचार, पत्तन और विमानपत्तन के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के सेवा प्रदायकों के निगमीकरण के कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ेंगे।

49. प्रधानमंत्री जी ने सङ्केत विकास के लिए एक बड़ी पहल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) की घोषणा की है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 54,000 करोड़ रुपए है। अपने पिछले बजट प्रस्तुत करते समय मैंने पेट्रोल और डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर का उपकर लगाने की घोषणा की थी और इसका काफी बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय

राजमार्ग विकास परियोजना के निधिकरण के लिए उपलब्ध होना अनुमानित है। परियोजना के वाणिज्यिक रूप से सक्षम घटकों के लिये संसाधनों को और बढ़ाने हेतु मुझे अपने भाषण के भाग 'ख' में कुछ और अधिक कहना है।

50. विद्युत क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आयोजना परिव्यय 7,626 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 9,194 करोड़ रुपए कर दिया गया है। टिहरी जल विद्युत और नाथपांडाकरी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय समर्थन बढ़ा दिये गए हैं ताकि ये दोनों परियोजनाएं मार्च 2002 तक चालू हो सकें। राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा उच्च-प्राथमिकता वाली परियोजनाएं चालू करने के लिए विद्युत वित्त निगम से ऋणों पर ब्याज सब्सिडी देने के लिए भी 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

51. विद्युत क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देने और पुराने तथा अक्षम संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण पर निवेश करने तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य संगठनों को सहायता प्रदान करने की एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के अधीन राज्य और संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों को 1,000 करोड़ रुपए की अंतिरिक्त केन्द्रीय आयोजना सहायता प्रदान की जाएगी।

52. राज्य विद्युत बोर्ड के पास केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत और कोयला संगठनों की भारी बकाया राशियां हैं। राज्य विद्युत बोर्ड को इन बकायों के निपटान के लिए सहायता देने हेतु केंद्र सरकार के समर्थन से इन बकायों के प्रतिभूतिकरण की एक योजना को अंतिम रूप दिया गया है। केंद्र सरकार का समर्थन राज्य विद्युत बोर्ड के प्रचालन में सुधारों से जुड़ा होगा।

53. माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि सेतुसमुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट की पूर्व और पश्चिम तटीय पत्तनों के बीच छोटा मार्ग प्रदान करने की क्षमता है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने परियोजना का विस्तृत संभाव्यता अध्ययन एवं पर्यावरणिक प्रभाव का आंकलन करने की अनुमति दे दी है, जिसकी कुल लागत 4.8 करोड़ रुपए है। मैंने इसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान कर दिया है।

54. सरकारी क्षेत्र के प्रति सरकार की नीति सुस्पष्ट है। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-

- संभावित रूप से चल सकने योग्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना तथा उन्हें पुनरुज्जीवित करना;
- सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों को पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता है उन्हें बन्द कर देना;
- यदि आवश्यक हो तो सभी कम महत्व वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की इक्विटी को 26% अथवा उससे कम करना; और
- कामगारों के हितों की पूर्ण सुरक्षा करना।

विनिवेश/निजीकरण/सरकारी क्षेत्र का पुनर्गठन

55. इस नीति के अनुरूप पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा 20 सरकारी क्षेत्र के

उपक्रमों के वित्तीय पुनर्गठन का अनुमोदन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने प्रचलनों को पुनर्गठित करने, अपनी उत्पादकता सुधारने में सफल रहे हैं और उनके कार्यनिष्ठादान में एकदम परिवर्तन आ गया है। माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि सरकार ने हमारे नवरत्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में से एक स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए एक व्यापक पैकेज का अनुमोदन हाल ही में किया है।

56. कई ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं जो रुग्ण हैं और पुनरुज्जीवित करने के योग्य नहीं हैं। इनके कामगारों और कर्मचारियों को स्वीकार्य सुरक्षा प्रदान करने के बाद इन उपक्रमों को बंद कर देना ही एकमात्र विकल्प रहता है। ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए खैचिक अलगाव योजना (वी.एस.एस.) की लागत की पूर्ति करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि के संसाधन पर्याप्त नहीं रहे हैं। परन्तु, इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्तियां हैं, जिन्हें अगर मुक्त और वसूल किया जाए तो इनका प्रयोग खैचिक अलगाव योजना के निधिपोषण के लिए किया जा सकता है। सरकार इन परिसंपत्तियों की प्रतिमूर्ति के एवज में बाजार से संसाधन जुटाने और इन निधियों का उपयोग कामगारों तथा कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिये करेगी।

57. सरकार ने हाल ही में विनिवेश एवं निजीकरण के लिए एक व्यवस्थित नीति तैयार करने और इस कार्यक्रम को नई गति देने के लिए एक नया विनिवेश विभाग स्थापित किया है जो चुने गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अनुकूल बिक्री पर अधिक जोर देगा। सभी गैर-महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी घटाकर 26 प्रतिशत या उससे कम की जाएगी तथा कामगारों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। विनिवेश एवं निजीकरण की संपूर्ण प्राप्तियों का उपयोग सामाजिक क्षेत्रकों के व्यय को पूरा करने, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन और सरकारी ऋण चुकाने में किया जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र

58. सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के तीव्र आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आधारभूत सुविधाओं विशेषकर विमानपत्तन, रेलवे, विद्युत और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि उत्तर-पूर्व के कई भागों में देखी गई पृथक्करण की भावना दूर की जा सके। व्यावसायिक शिक्षा के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगले दो वर्षों के भीतर उत्तर-पूर्वी राज्यों में 50 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 446 कम्प्यूटर सूचना केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

59. उत्तर-पूर्व में कृषि और बागान विकास की क्षमता का उपयोग करने के लिए लघु सिंचाई और बागवानी की स्कीमों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के विकास के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन पर भी विचार किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

60. अनुसूचित जातियों के लोगों के शैक्षणिक मानदंडों में सुधार लाने और उनकी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक स्तरोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम पर फिर से जोर दिया जाएगा। इस स्कीम के लिए बजटीय प्रावधान 72 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 130 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत महिला साक्षरता पर जोर दिया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में लगभग 6 लाख सफाई कर्मियों को उनके कार्य से मुक्ति दिलाने और उनके पुनर्वास के हमारे

राष्ट्रीय उद्देश्य की घोषणा की है। एक नयी कार्य योजना तैयार की जाएगी जिसके अन्तर्गत सफाई कर्मियों को स्व-सहायित सहकारिताओं में संगठित किया जाएगा और सरकार तथा सम्बन्धित वित्त विकास निगमों से सहायता प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक नया जनजातीय कार्य मंत्रालय स्थापित कर दिया गया है। इस मंत्रालय के आयोजना आवंटन को 684 करोड़ रुपए से पर्याप्त रूप में बढ़ाकर 810 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

वर्ष 1999-2000 के लिए संशोधित अनुमान

61. बजट के लिए यह कठिन वर्ष रहा है जिसमें व्यय अधिक बढ़ गया था और करों की वसूली में कुछ कमी आयी थी। बजटीय व्यय में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और बजटीय कर वसूली में 4 प्रतिशत की कमी का अनुमान है। आयोजना-भिन्न व्यय 17,461 करोड़ रुपए (2,06,882 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि) बढ़ गया है और आयोजना व्यय 2,395 करोड़ रुपए (77,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि) बढ़ गया है। आयोजना भिन्न व्यय में मुख्य बढ़ोत्तरी पेंशन भुगतानों (4,173 करोड़ रुपए), व्याज भुगतान (3,425 करोड़ रुपए), राज्यों को बढ़ाए गए अर्थोपाय अग्रिम (3,000 करोड़ रुपए), रक्षा (2,810 करोड़ रुपए), व्याज सक्षिदी (1,304 करोड़ रुपए), खाद्य सक्षिदी (1,000 करोड़ रुपए), डाक घाटा (848 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से राज्यों को सहायता (1,064 करोड़ रुपए) के कारण हैं। योजना व्यय के मामले में मुख्य बढ़ोत्तरी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास (1,900 करोड़ रुपए), राज्य सङ्करण (1,000 करोड़ रुपए), रेलवे सुरक्षा (200 करोड़ रुपए), जम्मू एवं कश्मीर को विशेष सहायता और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्यों को बढ़ी हुई सहायता के कारण है। विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के बजट से की गयी बचतों के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में परियोजनाओं/स्कीमों के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए रिलीज करने की आशा की जाती है।

62. 1,32,365 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधानों की तुलना में केन्द्र के निवल कर राजस्वों की प्राप्ति 1,26,469 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो लगभग 5,900 करोड़ रुपए की कमी को प्रदर्शित करता है। यह कमी मुख्यतः तेल-भिन्न आयातों के डालर मूल्य में अत्यधिक कम वृद्धि और वर्ष के अधिकांश समय में विनिर्मित उत्पादों के मामले में कम मुद्रा-स्फीति के परिणाम स्वरूप अपेक्षता कम उत्पाद राजस्व के कारण है। बजट के 10,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में विनिवेश प्राप्तियां 2,600 करोड़ रुपए होने की आशा है।

63. इस प्रकार राजकोषीय घाटा बजट के 4.0 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.6 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

वर्ष 2000-01 के लिए बजट अनुमान

64. वर्ष 2000-2001 के लिए बजट अनुमानों में, कुल व्यय 3,38,487 करोड़ रुपए अनुमानित है जिसमें से 88,100 करोड़ रुपए आयोजना के लिए और 2,50,387 करोड़ रुपए आयोजना-भिन्न व्यय के लिए है।

आयोजना व्यय

65. केन्द्रीय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए बजट सहायता 88,100

करोड़ रुपए रखी गई है, जो 1999-2000 के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा 8,705 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाती है। केन्द्रीय आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता 1999-2000 के संशोधित अनुमानों में 43,661 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 51,276 करोड़ रुपए की जा रही है। 1,17,334 करोड़ रुपए का कुल केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 96,310 करोड़ रुपए के पिछले स्तर से 21,024 करोड़ रुपए अधिक होगा जो कि 22 प्रतिशत की काफी अधिक वृद्धि है। वर्ष 2000-2001 के लिए आयोजना में बुनियादी आधारभूत सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिसमें ऊर्जा, परिवहन और संचार में कुल केन्द्रीय आयोजना परिव्यय का 60 प्रतिशत व्यय प्रस्तावित है। सामाजिक सेवाओं के लिए परिव्यय 1999-2000 के संशोधित अनुमान की तुलना में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

66. वर्ष 2000-2001 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की केन्द्रीय आयोजना सहायता 1999-2000 के संशोधित अनुमानों में 35,735 करोड़ रुपए की तुलना में 36,824 करोड़ रुपए रखी गई है।

आयोजना-भिन्न व्यय

67. वर्ष 1999-2000 के संशोधित अनुमानों में 2,24,343 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2000-2001 में आयोजना भिन्न व्यय 2,50,387 करोड़ रुपए होने का अनुदान है जो 26,044 करोड़ रुपए की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। आयोजना भिन्न व्यय में यह वृद्धि मुख्यतः रक्षा (10,083 करोड़ रुपए), व्याज भुगतान (9,841 करोड़ रुपए) और राज्यों के अनुदान (9,392 करोड़ रुपए) में है। परन्तु यह वृद्धि खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी के मामले में अदा की जाने वाली धनराशि में कटौती से आंशिक रूप में प्रतिसंतुलित की जानी है।

68. खाद्य एवं उर्वरकों पर बड़ी सब्सिडी हमारे आयोजना-भिन्न व्ययों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस दर से सब्सिडी भुगतान बढ़ता जा रहा है, उनको कायम रखना सम्भव नहीं है। हमें अपनी सब्सिडियों को उन पर लक्षित करने की आवश्यकता है जो गरीब और जरूरतमंद हैं जबकि अन्य को उसके लिए भुगतान करना चाहिए जिसका वह उपभोग करते हैं। वार्तव में, हम सब्सिडी युक्त खाद्य उनको प्रदान करना चाहते हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं ताकि वह अपनी बुनियादी पोषणिक 'आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तदनुसार, अगले वर्ष से हम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्नों का आवंटन दुगना बढ़ाकर 10 किग्रा. से 20 किग्रा. कर रहे हैं। इससे हमारे सबसे गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा में अत्यधिक वृद्धि होगी। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का वितरण मूल्य किफायती लागत के 50 प्रतिशत पर निर्धारित किया जा रहा है जो सरकार द्वारा दिसम्बर, 1996 में, लिए गए निर्णय के अनुरूप है। इन उपायों का अगला खास प्रयोजन गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के आर्थिक खाद्य बजट को सुधारना और उनकी खाद्य सुरक्षा को अत्यधिक बढ़ाना होगा। साथ ही साथ गरीबी की रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए किफायती लागत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिक्री मूल्य निर्धारित करने के द्वारा ही यह उपलब्धि सम्भव है। चीनी के मामले में अब आयकर निर्धारितियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चीनी का आवंटन नहीं किया जाएगा। अन्य के लिए, चीनी के उगाही मूल्य में वृद्धि को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी का वितरण मूल्य 13 रुपए प्रति किलो निर्धारित

किया जा रहा है। इन उपायों के फलस्वरूप मैं खाद्यान्न तथा चीनी सब्सिडी पर व्यय 2000-2001 में 8,210 करोड़ रुपए पर रखने की आशा कर सकता हूँ।

69. उर्वरक सब्सिडी के मामले में, सदस्य इस बात से अवगत हैं कि हमारी वर्तमान प्रतिधारण मूल्य रकीम में अनेक कमियां हैं। अधिकांश सब्सिडी उत्पादकों को जाती हैं न कि किसानों को। हमारे उर्वरक यूनिटों की अधिक कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए अगले वर्ष से पूँजी संबंधित प्रभारों की अधिकतम रीमा निर्धारित करने सहित, प्रतिधारण मूल्य रकीम को कुछ युक्तिसंगत बनाने की योजना अमल में लाई जाएगी। रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय भी मध्यावधि में प्रतिधारण मूल्य रकीम को क्रमबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए रूपरेखा प्रकाशित करेगा। निवेशों की बढ़ती हुई लागत को ध्यान में रखने के लिए यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य 15 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। नियंत्रण मुक्त उर्वरक के मामले में रियायत की दर को भी कम किया जा रहा है। परन्तु मूल्यों के प्रभाव को संयमित करने के लिए डी.ए.पी और एम.ओ.पी का अधिकतम खुदरा मूल्य क्रमशः केवल 7 प्रतिशत और 15 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि इन परिवर्तनों और प्रतिधारण मूल्य रकीम की कुछ युक्तिसंगतता के कारण वर्ष 2000-2001 में उर्वरक सब्सिडी पर व्यय 12,651 करोड़ रुपए होगा।

70. ग्यारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2000-2001 में राज्यों को कर हस्तान्तरण तथा अनुदानों के अनन्तिम प्रबन्धों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने आयोग द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट में की गई संस्तुति के अनुसार राज्यों को अनुदानों के हस्तान्तरण का फार्मूला तथा धनराशि की मात्रा को स्वीकार कर लिया है और तदनुसार मैंने बजट में प्रावधान कर दिया है।

71. महोदय, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। मैं पहले अप्रत्यक्ष करों पर आता हूँ।

72. माननीय सदस्यों को अवगत है कि केन्द्र और राज्य दोनों अत्यधिक रूप से अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर करते हैं। मैंने हालांकि पिछले वर्ष उत्पाद शुल्कों की दरों की पुनर्संरचना के काम को बहुत हद तक अंजाम दिया था, फिर भी इस प्रक्रिया को आगे ले जाने की जरूरत है। करदाता के लिए अनुपालन लागत में कमी लाने के लिए हमें कर संरचना को पूरी तरह दुरुस्त करने और कार्यविधियों को युक्तिसंगत और सरल बनाने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कर विवादों में अपनी शक्ति नष्ट करने की बजाय उत्पादन बढ़ाने और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करें।

73. महोदय, उत्पाद शुल्क में मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य केन्द्र में एक एकल दर की केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर (सेनवैट) प्रणाली स्थापित करना है। मुझे विश्वास है कि इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता, इससे दीर्घकालिक स्थायित्वता प्राप्त होगी, उद्योग के मन की अनिश्चिततायें दूर होंगी और वर्गीकरण के विवाद समाप्त होंगे। इससे राज्यों को भी 1.4.2001 तक अपने बिक्री करों को मूल्यवर्धित कर (वैट) में परिवर्तित करने के अपने सम्मत कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।

74. सदन को स्मरण होगा कि अपने पिछले बजट में मैंने बुनियादी उत्पाद शुल्क की तीन मूल्यानुसार दरें अर्थात् 8%, 16% और 24% शुरू की थीं। मैं इन तीन मूल्यानुसार दरों को 16% 'सेनवैट' की एक दर में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

75. इस प्रकार 8% की उत्पाद शुल्क दर समाप्त की जा रही है और इस दर वाली अधिकांश मर्दे 16% में लाई जा रही हैं। फिर भी कुछ मर्दों को, जो अनिवार्यतः चिकित्सा देखरेख

एवं आम आदमी के उपयोग की हैं, उत्पाद शुल्क से छूट दी जा रही है। वे मर्दें इस प्रकार हैं:

चिकित्सीय मर्दें

- * औषधीय ग्रेड आक्सीजन
- * औषधीय ग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड
- * वेदना-हारक
- * पोटेशियम आयोडेट
- * चिकित्सीय एवं सर्जीकल ग्लोब्स और

आम उपयोग की मर्दें

- * कटलरी एवं चाकू-छुरी
- * घरेलू उपयोगी ग्लासवेयर जिसमें माउथ-ब्लोन प्रक्रिया से बने ग्लासवेयर भी शामिल हैं।
- * प्रति बल्ब 20 रुपए तक के अधिकतम खुदरा मूल्य वाले विद्युत बल्ब
- * प्रति अदद 500 रुपए तक के अधिकतम खुदरा मूल्य वाली दीवार घड़ियां एवं घड़ियां
- * टूथ पाउडर
- * सेनिटरी टावल्स, शिशुओं के नैपकिन्स आदि, और
- * सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु साबुन।

76. मैं भुनी हुई चिकोरी को भी छूट प्राप्त मर्दों में शामिल कर रहा हूं क्योंकि रखयं कॉफी उत्पाद शुल्क से मुक्त है।

77. मैंने बड़े सार्वजनिक हित में विनिर्दिष्ट शीतागार शृंखला उपस्करों, जिसके लिए मैंने पिछले बजट में 8 प्रतिशत की कम दर की व्यवस्था की थी, को उत्पाद शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया है।

78. कुछ मर्दें अपनी असाधारण प्रकृति एवं मूल्य वृद्धि के प्रति संवेदनशील होने के कारण कम से कम इस समय विशेष संव्यवहार के योग्य हैं। ये मर्दें मिट्टी तेल, एल.पी.जी., धुलाई साबुन, कपास धागा, सूती सिलाई धागा और धागों की कुछ अन्य किस्में तथा 10 अश्व शाकित तक के डीजल इंजन हैं। अतः इनके लिए दर संरचना इस तरह बनाई जा रही है कि 8% के वर्तमान स्तर से इनमें उत्पाद शुल्क न बढ़े और इस प्रकार इस वजह से मूल्य वृद्धि नहीं होगी।

79. जिन मर्दों पर इस समय 16% उत्पाद शुल्क है, उनकी सूची में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है।

80. 16% की 'सेनवैट' दर के अलावा मैं विशेष उत्पाद शुल्क की 8%, 16% और 24% की तीन विशेष दरों का प्रस्ताव करता हूं। 'सेनवैट' दर से भिन्न यह विशेष उत्पाद शुल्क सामान्यतया मोडवैट योग्य नहीं होंगे अर्थात् उपयोगकर्ता इन शुल्कों के लिये मोडवैट क्रेडिट प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

81. लगभग उन सभी मर्दों पर जो कच्चे माल या मध्यवर्ती किस्म के हैं, 16% की 'सेनवैट' दर लगाई जाएगी। अतः मैं प्लास्टिक सामग्री, प्लास्टिक की फिल्म और शीटों, ट्रीड-रबर, सेलुलर रबर, रबर की वस्तुओं, नाइलोन फिलामेंट यार्न, वस्त्र सामान से बनी ट्रांसमिशन एवं कन्वेयर बेल्ट और सिंथेटिक वस्त्र सामग्री से बनी बोरियों एवं थैलों को वर्तमान 24% के स्तर से 16% 'सेनवैट'

की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं ओ.ई. आपूर्तियों के लिए टायरों एवं वातानुकूलन तथा प्रशीतन मशीनरी के पार्ट्स को भी उन पर कोई विशेष उत्पाद शुल्क लगाए बिना 16% 'सेनवैट' वाली सूची में शामिल कर रहा हूँ क्योंकि उत्पादन श्रृंखला में यह मध्यवर्ती माल में आते हैं।

82. इसके अलावा मैं कुछ अन्य उत्पादों, जिन पर इस समय 24% का शुल्क लगाया जाता है, पर शुल्क का बोझ कम कर रहा हूँ। यह मद्दें स्टेराइल कानटेक्ट लैंस सोल्यूशन, योगजरहित शिकाकाई पाउडर, शारीरिक-विकलांगों के लिए कारें हैं। मैंने विचार किया है कि इन मद्दों पर 16% 'सेनवैट' से अधिक का शुल्क भार नहीं डाला जाना चाहिए।

83. पंजीकृत अस्पतालों द्वारा खरीदी गई एम्बुलेंसों पर इस समय 16% का रियायती शुल्क दर लगाया जाता है। मैं भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा खरीदी गई एम्बुलेंसों के साथ भी यही व्यवहार कर रहा हूँ।

84. जिन अन्य मद्दों पर इस समय 24% शुल्क लगाया जाता है उन पर यह इतना ही बना रहेगा अर्थात् 16% 'सेनवैट' और 8% विशेष उत्पाद शुल्क।

85. उत्पाद शुल्क संरचना की मेरी नई योजना में उन मद्दों पर जिन पर इस समय कुल 30% शुल्क लगाया जाता है, कुल 32% शुल्क लगाया जाएगा अर्थात् 16% 'सेनवैट' और 16% विशेष उत्पाद शुल्क। यह मामूली तौर पर केवल 2% की वृद्धि है और मुझे विश्वास है कि इन वस्तुओं के उपभोक्ता इतना बहन कर सकते हैं।

86. इस समय कुल 40% शुल्क वाली मद्दों पर अब 16% 'सेनवैट' और 24% विशेष उत्पाद शुल्क होगा। परन्तु बोटलर्स को आपूर्ति किए गए मृदु पेय सान्द्रण पर केवल 16% की दर से 'सेनवैट' लगाया जाएगा जो मोडवैट योग्य होगा।

87. अब मैं मोडवैट स्कीम और उन परिवर्तनों जो मैं करना चाहता हूँ, का उल्लेख करूँगा। 'मोडवैट' स्कीम को अब 'सेनवैट' स्कीम से जाना जाएगा।

88. गत वर्षों में विभाग और कर-निर्धारितियों के बीच मोडवैट नियमावली की व्याख्या और प्रक्रियाओं पर विवादों ने प्रणाली के लिए परेशानी उत्पन्न की है। मैं इस स्थिति को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। अब 1 अप्रैल, 2000 से विद्यमान नियमों की बहलता के स्थान पर एक सरल एवं स्पष्ट नियमों का एक छोटा सेट होगा जो मैं आशा करता हूँ कि विवादों को कम से कम करेगा।

89. मैं मोडवैट स्कीम के दायरे के विस्तार एवं युक्तिसंगतता का प्रस्ताव करता हूँ। सभी सामग्रियों एवं सभी पूँजीगत मालों को मोडवैट स्कीम के योग्य सूची में शामिल करता हूँ। इसका अपवाद केवल उच्च गति डीजल तेल (एच.एस.डी.) एवं पेट्रोल होगा। परन्तु मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मोडवैट क्रेडिट की पूँजीगत मालों पर उपलब्धता 1 अप्रैल, 2000 से दो वर्ष के लिये होगी।

90. मेरे प्रस्तावों में पहली बार सिगरेटों के लिए मोडवैट स्कीम पूरी तरह लागू करना शामिल है जिसका उद्योग को स्वागत करना चाहिए। परन्तु सिगरेट विनिर्माताओं के लिए इससे आगे शुभ समाचार नहीं है। मैं सभी किस्म की सिगरेटों पर 5% उत्पाद शुल्क की दर बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

91. इस समय परियोजना आयातों पर प्रदत्त सी.वी.डी. का मोडवैट क्रेडिट 75% तक सीमित है। यह एक परेशानी का विषय रहा है। यह क्रेडिट अब सी.वी.डी. के 100% के लिए उपलब्ध होगा। मैंने पूंजीगत माल पर क्रेडिट लेने की पूर्वापेक्षा के रूप में संस्थापन की शर्त को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है।

92. अब कुछ क्षेत्रक विशिष्ट प्रस्तावों का उल्लेख किया जाएगा। इसमें सबसे पहले इस्पात है।

93. अध्यक्ष महोदय, कराधान की मूल्य आधारित संरचना अधिकांशतः विकृतियों से मुक्त, समान एवं स्वतः बढ़ने वाली है। इस समय मैं रि-रालर्स और 'इन्डक्शन फर्नेसेस' द्वारा उत्पादित इस्पात पर मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क संरचना बहाल करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन मालों पर 1 अप्रैल, 2000 से मोडवैट लाभ के साथ 16% का 'सेनवैट' लगाया जाएगा। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि रि-रालर्स और 'इन्डक्शन' फर्नेसेस पर लागू क्षमता आधारित कर ने समस्याएं सुलझाने के बजाए अधिक समस्याएं उत्पन्न की हैं।

94. विद्यमान कानून के अधीन डिपो से बेचे गए माल पर डिपो मूल्य के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है न कि फैक्ट्री मूल्य पर। मुझे प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इससे इस्पात की विपणनीयता और वितरण में विकृतियां उत्पन्न हुई हैं। एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा इस्पात की डिलीवरी चाहे संयंत्र से की गई हो या स्टाकयार्ड, से उसके उत्पाद शुल्क का निर्धारण अब आगे से फैक्ट्री मूल्य पर किया जाएगा।

95. महोदय, अब मैं वस्त्र उद्योग पर आता हूँ।

96. मैंने दिसम्बर, 1998 में स्वतंत्र वरन्त्र-प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए सम्मिलित शुल्क स्कीम शुरू की थी। यह आशा के अनुरूप कार्य नहीं कर पाई और इससे नुकसान एवं राजस्व हानियां हुईं, अभी भी मैं इस स्कीम में एकदम परिवर्तन नहीं चाहता। परन्तु स्थिति को सुधारने के लिये मैं सम्मिलित शुल्क की दरें प्रति चैम्बर प्रतिमास 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति चैम्बर प्रतिमास 2 लाख रुपए और वर्तमान 2 लाख रुपए से प्रति चैम्बर प्रतिमास 2.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। मेरे प्रस्तावों में स्कीम में कुछ संशोधन भी शामिल हैं ताकि कमियों को दूर किया जा सके।

97. शुल्क प्रदत्त पोलिएस्टर यार्न की बुनाई (टैक्सटराइजिंग) में संलग्न यूनिटें अब आगे से उत्पाद शुल्क की विशिष्ट दर पर भुगतान करेंगी। इससे इन यूनिटों के संबंध में मूल्य-निर्धारण विवाद कम होने चाहिए।

98. लघु इकाइयों को एक वर्ष में 50 लाख रुपए तक की निकासियों पर शुल्क रहित छूट प्राप्त है। मैं इस सीमा को बढ़ाने में असमर्थ हूँ। तथापि, 1 अप्रैल, 2000 से मैं शृंगार और प्रसाधन सामग्रियों, बातानुकूलन और प्रशीतन मशीनरी और उनके पुर्जों, ट्रीड रबर और प्लास्टिक के सामान के लिए प्रचलित विशेष स्कीमों को युक्तिसंगत बना कर उन्हें लघु इकाइयों के लिए छूट की सामान्य स्कीम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव करता हूँ।

99. महोदय, अब मैं अपने प्रस्तावों की अगली बात पर आता हूँ जो प्रणाली को सुप्रवाही और सरल बनाने से संबंधित हैं। इनका उद्देश्य उत्पाद शुल्क कार्यविधियों की जटिलताओं और कठोरताओं के जाल से निकाल कर उन्हें सरल और उपभोक्ता के अनुकूल बनाना है। मैं यह भी

कहना चाहूंगा कि मेरे दर संबंधी प्रस्तावों की ही तरह ये प्रस्ताव भी छोटे-छोटे समायोजनों अथवा सुधारों से कहीं आगे हैं और वर्तमान पद्धतियों से मूलभूत और यहां तक कि नाटकीय बदलाव को प्रदर्शित करते हैं।

100. 1 जुलाई, 2000 से उत्पाद शुल्क के सभी सांविधिक अभिलेखों को समाप्त कर दिया जाएगा। उत्पाद शुल्क विभाग विनिर्माताओं के अभिलेखों पर निर्भर करेगा। इस संबंध में मेरे द्वारा पिछले बजट में आरंभ की गई प्रक्रिया को यह पूरा करता है।

101. 1 अप्रैल, 2000 से उत्पाद शुल्क निर्धारितियों को उत्पाद शुल्कों की अदायगी पाक्षिक किश्तों में करने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रस्ताव से मैं उत्पाद शुल्कों के दिन-प्रतिदिन अदायगी की बहुत पुरानी पद्धति को समाप्त कर रहा हूँ। लघु क्षेत्रक के लिए मेरे द्वारा पिछले वर्ष शुरू की गई मासिक अदायगी योजना जारी रहेगी।

102. इसके बाद मैं मूल्यांकन प्रणाली को सरल, प्रयोक्ता के अनुकूल और वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य रूप में बनाना चाहता हूँ। 1 जुलाई, 2000 से मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की विद्यमान धारा 4 जो 'सामान्य मूल्य' की अवधारणा पर आधारित है, के स्थान पर कर-निर्धारण के लिए 'सौदा मूल्य' के अंगीकरण पर आधारित नई धारा लाना चाहता हूँ। यह परम्परागत नीतियों से हटकर एकदम दूसरे मार्ग पर बढ़ने जैसा है।

103. सदन इस बात से अवगत है कि कई मदों पर उत्पाद शुल्क का निर्धारण अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर किया जाता है। यह प्रणाली लगभग विवादों से परे है और इसका उद्योग जगत में आमतौर पर ख्वागत हुआ है। मैं अधिकतम खुदरा मूल्य पर आधारित निर्धारण को दो दर्जन नई मदों पर लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। मेरा वर्ष के दौरान और मदों को इस रकीम के अंतर्गत लाने का भी प्रस्ताव है।

104. मैं औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम के अधीन औषधीय और प्रसाधन उत्पादों पर लागू शुल्कों की दरों को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव करता हूँ। अधिकतम खुदरा मूल्य आधारित कर निर्धारण उपबंधों का इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के लिए भी विस्तार किया जा रहा है। इन उपायों से राज्यों द्वारा उत्पाद शुल्क का संग्रहण अत्यधिक आसान हो जाएगा और उनके राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। ये परिवर्तन किसी अधिसूचित तारीख से लागू होंगे।

105. उपरोक्त के अतिरिक्त मैं चूक की स्थिति में ब्याज और दण्ड की अदायगी से संबंधित उपबंधों को युक्तिसंगत बनाने रहा हूँ। इसके ब्यौरे वित्त विधेयक में निहित हैं।

106. यहां मेरा उत्पाद शुल्क की पुनर्संरचना और यौक्तिकीकरण से संबंधित पैकेज पूरा होता है। व्यापार एवं उद्योग को अब राहत की सांस लेनी चाहिए।

107. अब मैं सीमा शुल्क से संबंधित अपने प्रस्तावों पर आता हूँ।

108. मुझे मालूम है कि इस क्षेत्र में मेरे सामने गम्भीर अड़चने हैं। हमें देशी उद्योग को पर्याप्त संरक्षण और विकास प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों की टैरिफ-व्यवस्था को अनुसंशोधित करने के बीच एक विवेकयुक्त संतुलन बनाए रखना है। हमें सुधार और यौक्तिकीकरण की प्रक्रिया को और आगे ले जाने की भी जरूरत है।

109. सभी कारकों पर विचार करते हुए, मैं बुनियादी शुल्क की अधिकतम दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने और इस प्रकार सीमा शुल्क की दरों की कुल संख्या को 5 से घटाकर 4 अर्थात् 35 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

110. 10 प्रतिशत का अधिभार, जिसे मैं राजस्व की मजबूरियों के चलते जारी रखने पर विवश हूँ 35 प्रतिशत की नई अधिकतम दर पर लागू होना जारी रहेगा। कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों, विश्व व्यापार संगठन करार में शामिल कुछ मदों और सोने और चांदी पर छूट बनी रहेगी।

111. सदन को यह स्मरण होगा कि मैंने वर्ष 1998-99 के अपने बजट प्रस्तावों में सीमा शुल्कों का एक विशेष अतिरिक्त शुल्क (सैड) लगाया था। इससे विनिर्माता आयातकर्ताओं में काफी उदासी फैल गई थी। परन्तु व्यापारी खुश थे, क्योंकि उन्हें छोड़ दिया गया था। मैं इस छूट को वापस लेकर इस भेदभाव को दूर कर रहा हूँ। अब सभी आयातक यह शुल्क अदा करेंगे। परन्तु विशेष अतिरिक्त शुल्क पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू नहीं होगा।

112. हमारी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संधि दायित्वों के परिणामस्वरूप कई सौ मदें 1.4.2000 से आयातों की निःशुल्क सूची में रखी जाएंगी। इनमें से अधिकांश उपभोक्ता वस्तुएं हैं और अनेक कृषि उत्पाद हैं। इन मदों को पर्याप्त टैरिफ संरक्षण प्रदान करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं जैसी कुछ मदों को छोड़कर उन्हें अधिकतम दर (35 प्रतिशत तथा अधिभार) पर रखा जा रहा है। कई कृषि और बागवानी उत्पादों, जिन्हें गत वर्षों में आयात की निःशुल्क सूची में रखा गया था, को भी हमारे किसानों के पर्याप्त संरक्षण के लिए अधिकतम दर में लाया जा रहा है।

113. इसके अतिरिक्त थोड़े से संवेदनशील कृषि उपजों (गेहूँ चावल, चीनी और खाद्य तेल) जिनमें आपूर्ति प्रबन्धन के हमारे अनुभव ने समय-समय पर टैरिफ समायोजनों के महत्व को रेखांकित किया है, मैं उपयुक्त रूप से उच्च रस्तों पर सांविधिक टैरिफ दरों को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त सामर्थ्यकारी उपबंध कर रहा हूँ। इससे लागू दरों के समायोजन के लिए आवश्यक लचीलापन मिल सकेगा।

114. सीमा शुल्क राजस्व उगाही का जरिया ही नहीं है, यह हमारी औद्योगिक क्षमताओं का निर्माण करने और हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली साधन है। मैं इस संबंध में अनेक उपायों का प्रस्ताव करता हूँ जिनमें तीन क्षेत्रकों को चुना जा रहा है जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना है। ये 'समविकासिता क्रान्ति' जो तेजी से एक वास्तविकता बन रही है, का भी अभिन्न अंग है।

115. सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) क्षेत्रक है जो वर्तमान हलचल के माहौल में अग्रणी है। मैं आई टी क्षेत्रक के लिए कई मदों पर सीमा शुल्क घटाने का प्रस्ताव करता हूँ। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- * कम्प्यूटर, 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत;
- * मदर बोर्ड, 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत;
- * फ्लॉपी डिरक, 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत;
- * सेमिकंडक्टरों और आई सी के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुएं 15 प्रतिशत से 5 प्रतिशत;

- * कम्प्यूटरों के लिए माइक्रोप्रोसेसर, 5 प्रतिशत से शून्य;
- * मेमोरी स्टोरेज उपकरण, 5 प्रतिशत से शून्य;
- * सीडी रोम 5 प्रतिशत से शून्य;
- * इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रोएसेम्बलीज 5 प्रतिशत से शून्य; और
- * कम्प्यूटरों के लिए रंगीन मॉनीटरों के लिए डाटा ग्राफिक डिस्प्ले टच्यूब 5 प्रतिशत से शून्य;

116. दूरसंचार भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए हमें देश और विदेशों से जुड़ना होगा। अतः मैं आप्टिकल फाइबर के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्चे माल पर बुनियादी सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं सेल्युलर फोनों पर शुल्क को 25 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूँ जिससे उनकी उचित माध्यमों से उपलब्धता में सुधार लाया जा सके और अनियमित बाजार के खतरे को रोका जा सके और उनके बैटरी पैकों पर सीमा शुल्क 40 प्रतिशत से 15 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। मैं विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर लागू बुनियादी शुल्क की 5 प्रतिशत की रियायती दर को इंटरनेट सेवा प्रदायकों के लिए भी लागू कर रहा हूँ।

117. तीसरा क्षेत्र मनोरंजन उद्योग है और यह भी वृहत् सम्भावना का क्षेत्र है। फिल्म उद्योग के लिए सिनेमाटोग्राफी की लागत में कमी करने और नवीनतम प्रौद्योगिकी तक पहुँच बनाने के लिए मैं सिनेमाटोग्राफी कैमरों और अन्य संबंधित उपकरणों पर शुल्क 40 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं जम्बो रोलों में रंगीन पाजिटिव फिल्मों और कुछ आकारों के रोलों में रंगीन निगेटिव फिल्मों पर बुनियादी सीमा शुल्क भी 15 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन्हें भी सीधीड़ी से छूट प्राप्त होगी।

118. मैं इस संदर्भ में एक और क्षेत्रक को शामिल करना चाहूँगा।

119. भारत आभूषणों के निर्यात में विश्व में अग्रणी हो सकता है जैसे कि यह रत्नों के मामले में है। मैं उत्कृष्ट आभूषणों के उत्पादन को बढ़ावा देने और आभूषण निर्यात में तेजी लाने के उद्देश्य से प्लेटिनम और गैर-औद्योगिक हीरों पर बुनियादी सीमा शुल्क को 40 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

120. यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य के साथ हमारे करार को कार्यरूप देने के लिए, मैं फाइबर, यार्न, टेक्सटाइल फेब्रिक और वस्त्रों पर सीमा शुल्कों में समायोजन का प्रस्ताव करता हूँ। इसके परिणामस्वरूप, फेब्रिकों और वस्त्रों की कई किरमों पर अब से उनके लिए निर्धारित शुल्कों के यथा-मूल्य और विशेष दरों से अधिक शुल्क लगेगा।

121. जहां तक पेट्रोलियम क्षेत्रक का संबंध है, कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की पिछले कुछ समय से चल रही अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें अब हमारी पेट्रोलियम रिफाइनिरिंगों पर गम्भीर दबाव डालती आ रही हैं और इससे तेल पूल खाते में भी विकृतियां उत्पन्न हो गयी हैं। इसके बढ़ने का कारण यह भी है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अभी तक पूर्णतया नियंत्रण मुक्त नहीं की गयी हैं। इसलिए मैं कच्चे तेल पर बुनियादी सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने और पेट्रोलियम उत्पादों पर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें समानान्तर विपणन हेतु मिट्टी के तेल को शामिल नहीं किया गया है जिस पर बुनियादी शुल्क को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया जा रहा है।

122. कई मामलों में आबद्ध दरें हमारी अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता के भाग के रूप में घटाई जानी हैं। मैं उनके सम्बन्ध में विस्तार में जाकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। परन्तु इनकी कुछ राजस्व संबंधी उलझनें हैं।

123. अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष मैंने सामरिक स्वरूप की वस्तुओं अथवा चेरिटेबल उद्देश्यों को छोड़कर सीमा शुल्कों और उत्पाद शुल्कों में तदर्थ रियायत प्रदान करने की सरकार की शक्ति को समाप्त करने का प्रस्ताव किया था, मुझे सदन को यह सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि इस आत्म निषेधात्मक कानून से इस वर्ष लगभग 500 करोड़ रुपए की सरकारी बचत हुई है।

124. मैं अब प्रक्रियात्मक सुधारों तथा करदाताओं की समस्याओं के समाधान सम्बन्धी कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख करूँगा। सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तथाकथित 'कारण बताओ नोटिस राज' को कम करने के लिए मैंने निर्णय लिया है कि अब से ऐसे 'कारण बताओ नोटिस' जिनमें 1 करोड़ रुपए से अधिक की शुल्क राशि अन्तर्निहित हो, केवल सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे। अन्य 'कारण बताओ नोटिसों' के लिए सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

125. इसमें कोई विवाद नहीं है कि किसी चूककर्ता से प्राप्त कर लोकहित में यथाशीघ्र राजकोष में पहुँचना चाहिए। इस समय अपवंचित शुल्क के लिए 100 प्रतिशत के बराबर दण्ड की अदायगी करनी होती है और यह अनिवार्य है, भले ही कोई व्यक्ति अधिनिर्णयन आदेश दिए जाने के तत्काल बाद देयताओं का भुगतान करे। देय कर की अदायगी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मैंने अब प्रस्ताव किया है कि यदि आदेश के सूचित किए जाने के 30 दिन के भीतर अपवंचित कर की राशि की व्याज सहित अदायगी कर दी जाय तो केवल अपवंचित कर के 25 प्रतिशत के बराबर अनिवार्य दण्ड अदा करना होगा। मुझे आशा है कि यह दण्ड और प्रोत्साहन दोनों का उद्देश्य पूरा करेगा क्योंकि समय पर कर भुगतान न करने पर दण्ड लगाना ही होगा।

126. सेवा कर एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर रहा है जो सम्भावनाओं के द्वार खोलने के साथ-साथ समस्याओं को भी आमन्त्रण देता है। कई विशेषज्ञ मुझे सलाह देते हैं कि इस कर को व्यवहार में लाने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि इसे एक ही बार में सभी सेवाओं पर लागू कर दिया जाय। परन्तु कुछ अन्य ने सेवा कर के ढांचे में ही बुनियादी परिवर्तनों का सुझाव दिया है। मैंने फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय किया है। मैं मामले के सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने, अब तक के अनुभव की समीक्षा करने और अपनी सुविचारित सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन कर रहा हूँ।

127. उत्पाद शुल्क सम्बन्धी मेरे प्रस्तावों से एक वर्ष में 3252 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान है। सीमा शुल्क के सम्बन्ध में मेरे प्रस्तावों से 1428 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होने का अनुमान है।

128. सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्कों में परिवर्तनों को लागू करने वाली जारी अधिसूचनाओं की प्रतियां सदन के पटल पर यथा-समय रख दी जाएंगी।

129. अब मैं प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी प्रस्तावों की ओर आता हूँ।

130. अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों की मेरी योजना स्थायित्व, आर्थिक विकास, यौक्तिकीकरण और सरलीकरण इन चार बातों पर आधारित है।

131. वैयक्तिक कराधान की हमारी मौजूदा दरों की संख्या केवल तीन है और जो काफी कम हैं। यद्यपि प्राथमिक छूट सीमा 50,000 रुपए है, लेकिन जब अन्य छूट और कटौतियों को ध्यान में रखा जाए तो वास्तविक छूट सीमा कहीं अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए वेतनभोगी व्यक्ति मानक कटौती के कारण प्रतिवर्ष 75,000 रुपए की सीमा को पार करने के बाद ही कर का भुगतान करना प्रारम्भ करते हैं। यदि बचतों के लिए उपलब्ध कर रियायतें तथा कटौतियों को ध्यान में रखा जाए तो छूट की वास्तविक सीमा 1 लाख रुपए के आस-पास पहुंच जाती है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि कराधान की मौजूदा दरें तथा छूट सीमा उचित हैं। इसलिए मैं उन्हें उसी स्तर पर रखने का प्रस्ताव करता हूं।

132. यद्यपि पिछले वर्ष लगाया गया 10 प्रतिशत अधिभार अस्थायी था, लेकिन मुख्यतः रक्षा आवश्यकताओं और वित्त आयोग द्वारा अधिदेशित राज्यों को हस्तान्तरण के कारण भारी और अप्रत्याशित व्यय भार को ध्यान में रखते हुए मैं इसे जारी रखने के लिए विवश हूं।

133. वर्ष के दौरान जब कारगिल कर की काफी बातें हो रही थीं मैंने कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया। मैं अब ऐसे गैर-कम्पनी करदाताओं पर अधिभार 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी कुल कर योग्य आय 1,50,000 रुपए से अधिक है। इससे उनकी सीमान्त दर में मामूली बढ़ोत्तरी होकर वह 33 प्रतिशत से 34.5 प्रतिशत हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि समाज का अपेक्षाकृत समृद्ध वर्ग इस अतिरिक्त भार को खुशी से वहन करेगा।

134. कहीं ऐसा महसूस न हो कि कम्पनियों पर अधिभार को न बढ़ाते हुए मैं भेदभाव बरत रहा हूं। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन कम्पनियों को भी अन्य प्रकार से अभी बाद में राष्ट्रीय प्रयास में अपना योगदान प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

135. वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद, मैं वैयक्तिक कराधान के सम्बन्ध में कुछ सकारात्मक उपायों का प्रस्ताव करता हूं।

136. वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अपनी सक्रियता की अवधि के दौरान दिए गए योगदान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने और बढ़ती उम्र में उनके द्वारा उठायी जाने वाली सम्भावित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मैं उनके लिए उपलब्ध कर रियायत को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। 30 प्रतिशत की सीमान्त कर दर पर, यह उनकी सकल आय से 15,000 रुपए की अतिरिक्त छूट है अथवा यह धारा 88 के अन्तर्गत सदृश छूट प्राप्त करने के लिए 25,000/-रुपए की अतिरिक्त राशि बचाने की आवश्यकता के स्थान पर है।

137. मैं हमेशा यह मानता आया हूं कि समस्त कठिनाइयों के बावजूद वित्त मंत्री के रूप में बजट बनाने का मेरा कार्य उस सामान्य गृहिणी की अपेक्षा सरल है जो परिवार का बजट संतुलित करने हेतु संघर्षरत है। अर्थव्यवस्था में एक उत्पादक भागीदार के रूप में महिलाओं के योगदान के महत्व को समझते हुए मैं प्रतीक रूप में, महिला करदाताओं को उनकी कर देयता से 5,000 रुपए की अतिरिक्त छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। यह छूट 15,000 रुपए की समग्र सीलिंग के अधीन होगी, यदि वह वरिष्ठ नागरिक भी हों।

138. रक्षा बलों के सदस्यों द्वारा की गयी सेवाओं को महत्व देने की दृष्टि से और उनके असाधारण साहस एवं शौर्य के लिए हमारा आभार प्रकट करने के रूप में मैंने इन सेवाओं के वीरता पुरस्कार पाने वालों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन को कर से छूट प्रदान की थी। अब मैं राष्ट्रीय

और नागरिक सुरक्षा में लगे अद्वैतिक बलों और दूसरे बलों के वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वालों के लिए भी इसी प्रकार का लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

139. अब मैं आर्थिक विकास में सहायक के रूप में कराधान की भूमिका पर चर्चा करूँगा। ज्ञान पर आधारित उद्योग अग्रणी रूप में तेजी से उत्थर रहे हैं। उनके विकास में तेजी लाने, उनमें निवेश को प्रोत्साहन देने और जैसाकि अपने भाषण के भाग 'क' में मैंने उल्लेख किया है, मैं उद्यम पूँजी निधियों के सम्बन्ध में एक नयी व्यवस्था का प्रस्ताव करता हूँ। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं होंगी:

- i) उद्यम पूँजी निधि के लिए कर प्राधिकारियों की कोई स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।
- ii) 'पास थो' का सिद्धान्त उद्यम पूँजी निधियों के कर व्यवहार में लागू होगा, उनकी आय कर से मुक्त होगी, केवल उस दशा को छोड़कर जब इसे 'सेबी' के दिशानिर्देशों में निर्धारित समयावधि के भीतर वितरित नहीं किया गया हो। निवेशकों के पास उपलब्ध आय भी जो अन्यथा करयोग्य होगी, करमुक्त रखी जाएगी और जब कि उद्यम पूँजी निधि अपनी आय निवेशकों की वितरित करता है तो उसके द्वारा 20 प्रतिशत की दर से केवल एक बार कर का भुगतान किया जाएगा। यही दर अवितरित आय पर भी लागू होगी।

140. मुझे आशा है कि इन प्रोत्साहनों से उद्यमियों तथा निवेशकों पर सरस्वती (अर्थात् ज्ञान) और लक्ष्मी (अर्थात् धन) का एक साथ वरदहस्त बना रहेगा।

141. आधारभूत क्षेत्रक के लिए पहले से ही कई कर लाभ उपलब्ध हैं। मैं इन लाभों का विस्तार शहरी अवसंरचना के दो अतिरिक्त और अत्यावश्यक क्षेत्रों अर्थात् जलशोधन और ठोस कूड़े-कचरे के निपटान पर करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं चेरिटेबल ट्रस्टों में स्वीकृत निवेश के रूप में शहरी अवसंरचना हेतु दीर्घकालिक वित्त पोषण की व्यवस्था करने वाली सार्वजनिक कम्पनियों में निवेशों को शामिल करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इससे शहरी अवसंरचना के विकास की परियोजनाओं में और अधिक निवेश करने में मदद मिलेगी।

142. आधारभूत सुविधा के विकास हेतु और अधिक प्रोत्साहन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए, मैं मौजूदा 54ड के और 54ड ख उपबंधों को हटाने और उनके स्थान पर नए उपबंध का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसके द्वारा पूँजीगत लाभों से प्राप्त कर रियायत तभी उपलब्ध होगी जब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा जारी किए गए बॉडों में निवेश किया गया हो। इन बॉडों की लॉक-इन अवधि पांच वर्षों की होगी और उनसे प्राप्त राशि का उपयोग कृषि के वित्त पोषण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) के लिये किया जाएगा।

143. मैं पिछले वर्ष आवास निर्माण के सम्बन्ध में दी गई सुविधाओं को जारी रखने और पहले से उपलब्ध लाभों को आगे दो वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ अर्थात् 31 मार्च, 2003 तक पूर्ण होने वाले मकानों अथवा परियोजनाओं पर यह लागू होगा। मुझे आशा है कि इससे आवास निर्माण की गतिविधियां बनी रहेंगी तथा उनमें तेजी आएगी।

144. इस क्षेत्र के प्रोत्साहन सम्बन्धी पैकेज को बढ़ाने के लिए, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि आयकर-अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत कर की 20 प्रतिशत छूट पूर्व में 10,000 प्रतिवर्ष की तुलना में अब 20,000 रुपए तक के लिये भवन निर्माण ऋणों की वापसी अदायगी हेतु उपलब्ध होगी।

145. वर्तमान में यदि पूँजी परिसम्पत्तियों के अन्तरण से प्राप्त पूँजी लाभ को किसी मकान में, यदि यह मकान पहले से ही स्वामित्व में हो, निवेशित किया जाता है तो दीर्घकालिक पूँजी लाभों पर कर से छूट की व्यवस्था नहीं है, मैं इस प्रतिबंध को हटा रहा हूँ। भले ही कर-दाता के पास एक मकान हो, तो भी वे नए मकान में निवेश कर सकते हैं और पूँजी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर प्राप्त पूँजी अभिलाभ पर कर से छूट का दावा कर सकते हैं।

146. गत वर्ष मैंने मनोरंजन उद्योग के लिए निर्यात लाभों पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का प्रावधान किया था। परन्तु यह लाभ केवल कम्पनियों तक सीमित रहा। मैं वित्तीय वर्ष 1999-2000 से इस लाभ को गैर-कम्पनी निर्धारितियों को भी प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे गैर-कम्पनी फिल्म निर्माताओं के प्रति नजर आ रहा भेदभाव दूर हो जाएगा, परन्तु मैं यह भी आशा करता हूँ कि यह उद्योग कम्पनीकरण तथा आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ेगा जो व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संभव है।

147. मनोरंजन उद्योग द्वारा लम्बे समय से की जा रही मांग पर ध्यान देने के लिए तथा प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने की दृष्टि से, मैं किसी फिल्म निर्माता द्वारा कर प्राधिकारियों को फिल्म निर्माण के दौरान भुगतान किए जा रहे मौजूदा 25,000 रुपए के स्तर को बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

148. मुझे विश्वास है कि प्रत्यक्ष कर के सम्बन्ध में पहले से दी गयी रियायतों के साथ ये रियायतें मनोरंजन उद्योग को इस बात से पुनः आश्वस्त करेंगी कि 'हम साथ-साथ हैं।'

149. नौ-परिवहन हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को परिवहन शाक्तियां प्रदान करता है और इसकी सामरिक प्रासंगिकता भी है। भारतीय नौवहन उद्योग, जो इस समय गम्भीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, के बेड़े को सृदृढ़ करने तथा इसका आधुनिकीकरण करने के लिए संसाधन पैदा करने में समर्थ बनाने हेतु मैं मौजूदा 50 प्रतिशत की तुलना में उसके सम्पूर्ण लाभों के सम्बन्ध में कटौती करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ यदि इन्हें नये जलयानों की खरीद के लिये उपयोग हेतु रिजर्व में रखा गया हो। यह 100 प्रतिशत की कटौती इस वर्ष से केवल पांच वर्ष तक के लिए उपलब्ध होगी।

150. मानव संसाधनों में निवेश सतत आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य प्राथमिकता है। प्रतिभावान, विशेषकर समृद्ध पृष्ठभूमि से नहीं आने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए मैं अनुमति योग्य कटौती के रूप में उच्च शिक्षा के लिए ऋण की वापसी अदायगी की अधिकतम राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह 3 लाख रुपए से अधिक को ऋण राशि में परिवर्तित करेगी, जिससे विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, विशेषकर प्रबंधन और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की बढ़ती हुई लागत पूरा करने में मदद मिलेगी।

151. व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपलब्धता बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में बहुत हद तक सहायक हो सकती है। यह एक तरफ व्यापक बेरोजगारी और दूसरी तरफ उचित रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी के बीच विरोधाभासी असमानता को भी दूर कर सकती है। इसे स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मैं छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षेत्रक द्वारा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए संरथाएं स्थापित करने और चलाने के लिए किए गए भुगतानों पर 100 प्रतिशत छूट की अनुमति देने का प्रस्ताव रखता हूँ।

152. कुछ महत्वपूर्ण परंतु छूट-पुट उपलब्धियों को छोड़कर हम अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में कोई बड़ा स्थान नहीं रखते। अन्य कई क्रियाकलापों की तरह आधुनिक खेलों को भी विकास के लिए मुद्रा और आधारभूत ढांचे की आवश्यकता होती है। जहां कई खेलों को अत्यधिक निधियां उपलब्ध हैं, वहां अन्य अधिकांशतः पर्याप्त सहायता के अभाव में कठिनाई में हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निगमित संगठनों द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास और खेलों की प्रायोजकता के लिए भारतीय ओलम्पिक संघ को दिए जाने वाले दान पर 100 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी। मैं आशा करता हूँ कि इस रियायत से भारतीय ओलम्पिक संघ देश में खेलों को बेहतर ढंग से बढ़ावा दे सकेगा।

153. पिछले वर्ष, निगमित पुनर्संरचना पर मेरे प्रस्तावों का भारतीय उद्योग द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया था। तथापि, कुछ उपबंधों को स्पष्ट करने और युक्तिसंगत बनाने की लगातार मांग होती रही है। अतः मैं आय-कर अधिनियम के उपबंधों में उपयुक्त परिवर्तन करके इस संबंध में अरपष्टता को दूर करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि राज्य विद्युत बोर्डों जैसे सांविधिक निकायों के विलगन के फलस्वरूप परिणामी कंपनियों को विलगन के लाभ प्राप्त होंगे, यदि वे केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तें पूरी करते हैं।

154. पिछले वर्ष मैंने घाटे को आगे ले जाने और समंजित करने के लिए समान कारोबार की निरंतरता की शर्त समाप्त कर दी थी। मैं उरी आधार पर असमायोजित मूल्यहास अग्रेनीत और समंजित करने से संबंधित उपबंधों को उदार बनाने का प्रस्ताव रखता हूँ। समान व्यापार की निरंतरता की शर्त समाप्त हो जाएगी और असमायोजित मूल्यहास को उस समान व्यापार के जारी नहीं रहने पर भी अग्रेनीत और समंजित किया जा सकेगा।

155. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित निगमों को अधिक पुनर्संरचना, लचीलापन और स्वतंत्रता देने के लिए मैं कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृति लाभों को और उदार बनाने तथा सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों पर कर छूट की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव रखता हूँ। अब उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के लिए उन्हें कर प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, अगर ये योजनाएं निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की जाती हैं।

156. न्यूनतम वैकल्पिक कर का परिकलन करते समय इस समय उपलब्ध विभिन्न छूटों और ऋण प्रणाली ने मौजूदा उपबंधों की कारगरता को कम आंका है और इससे कानूनी उलझनें भी उत्पन्न हुई हैं। इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि न्यूनतम वैकल्पिक कर अब 10.5 प्रतिशत की मौजूदा प्रभावी दर के बजाय कंपनी अधिनियम के अधीन यथानिर्धारित 'खाता लाभ' के 7.5 प्रतिशत की संशोधित दर पर लगाया जाए। तथापि, यह एक अपवाद, जिसका मैं बाद में उल्लेख करूँगा, को छोड़कर, अब समान रूप से लागू होगा। अदा किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर के लिए कोई खाता जमा भी नहीं होगा। इससे सभी शून्य करदाता कंपनियों को कर जाल के भीतर आ जानी चाहिए, जो इस कर का मूल प्रयोजन भी है। नई प्रणाली की विशेषता कर की निम्न दर, परिकलन की सरल विधि और समान रूप से प्रयोज्यता है।

157. कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगिकरण के संवर्धन के लिए मैं औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों और जिलों में रथापित नई इकाइयों के लिए उपलब्ध करावकाश को और दो वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी प्रकार, मैं नए स्थापित लघु उद्योगों के लिए मौजूदा कर लाभ अगले दो वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2002 तक प्रदान करने का प्रस्ताव भी करता हूँ।

158. हमारे पूंजी बाजार को सुदृढ़ करने के लिए मैं स्टॉक एक्सचेंजों की निवेशकर्ता संरक्षण निधियों की आय को ऐसी निधियां स्थापित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु 100 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

159. इस समय घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश आय पर शेयरधारकों द्वारा कोई कर देय नहीं होता है और कंपनी अपने द्वारा वितरित लाभांश की राशि पर 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त आय कर अदा करती है। लाभांश आय और ब्याज आय के कर निर्धारण में बड़े अंतर की व्यापक आलोचना की गई है। इस विसंगति को कम करने के लिए मैं घरेलू कंपनियों द्वारा वितरित लाभांशों पर कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूँ। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि शेयरधारकों को होने वाली लाभांश आय कर-मुक्त बनी रहेगी।

160. इसी तरह म्यूचुअल फंडों, बैंक जमाओं और कंपनी जमाओं जैसे अन्य साधनों से होने वाली ब्याज आय के लिए असमान कर निर्धारण से उत्पन्न विकृतियों को कम करने के लिए मैं ऋणोन्मुखी म्यूचुअल फंडों और यू टी आई द्वारा वितरित आय पर कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूँ। तथापि, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यू टी आई की यू एस-64 और अन्य खुली इक्विटी मूलक योजनाओं के अधीन वितरित आय को वर्तमान की तरह इस कर से छूट प्राप्त होती रहेगी।

161. इस समय बैंक और वित्तीय संस्थाएं 2 प्रतिशत का ब्याज कर अदा करती हैं जो उनकी लागतों में वृद्धि करते हैं। वित्तीय लेन-देनों में आने वाली इस बाधा को दूर करने के लिए मैं इस कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो वित्तीय क्षेत्रक को और उसके फलस्वरूप बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के उत्पादों और सेवाओं के उपयोगकर्ताओं और जमाकर्ताओं को लाभ पहुँचाएगा।

162. जीवन बीमा क्षेत्र को अब खोल दिया गया है और इस पर अब सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार नहीं रहेगा। इन पर अभी विशेष दर पर कर लगाया जाता है, जिसमें बदले हुए परिदृश्य में संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को देखते हुए ऐसा संशोधन करना चाहूँगा। मैं इस प्रयोजन के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव करता हूँ और वर्ष के दौरान इस संबंध में उसकी सिफारिशों के आधार पर आवश्यक संशोधन करने की आशा करता हूँ।

163. बेहतर कर अनुपालन की दिशा में की गई मुख्य पहलों में एक 1/6 योजना शुरू करना था। अन्य उपायों के साथ इसने करदाताओं, जो 1996-1997 तक मात्र प्रक्ष करोड़ से थोड़े अधिक स्तर तक ही सीमित थे, की संख्या बढ़ाने में काफी योगदान किया है और अब यह संख्या दो करोड़ से आगे पहुँच गई है जिसमें सबसे अधिक बढ़ोत्तरी पिछले दो वर्षों के दौरान हुई है। इससे उत्पन्न गति और कर आधार को व्यापक बनाने वाले अन्य उपायों को बनाये रखने की आवश्यकता है। अतएव मैं इस छः में से एक की योजना का मौजूदा 54 शहरों से देश के अतिरिक्त 79 देशों में विस्तार करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इससे वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर दो लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहर इसमें शामिल हो जाएंगे।

164. अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप चलने के लिये विभिन्न एजेंसियों और विभागों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले साझा व्यापारिक पहचान संख्या को बढ़ावा देना प्रस्तावित है। हमारे संदर्भ में आयकर की स्थायी खाता संख्या ऐसा एक दस्तावेज होगा। प्रारंभ में सीबीईसी और डीजीएफटी अपने निर्धारितियों, आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का

प्रयोग करेंगे। मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में काफी लोगों के लिए 'पैन' कार्ड प्राथमिक पहचान दस्तावेज के रूप में राशन कार्ड का स्थान लेगा।

165. 'पैन' आवंटन के अभियान को तेज करने की दृष्टि से मैं उन सभी शहरों, जहां छ: में से एक योजना चालू है, (उन 79 शहरों सहित जहां योजना का विस्तार किया जा रहा है) में करदाताओं द्वारा आवेदन दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर उन्हें 'पैन' कार्ड जारी करने के लिए विशेष काउंटर खोलने का प्रस्ताव करता हूं। यह सुविधा 1 जुलाई, 2000 से प्रारम्भ हो जाएगी।

166. महानगरों और बड़े शहरों के आसपास कई फार्महाउस स्थापित किए गए हैं। इनमें से कई को रिहायशी आवास के लिए किराए पर देने और समारोह आयोजित किए जाने से वाणिज्यिक आय होती है। इस आय, जिसकी कृषि आय के रूप में गलत घोषणा की जाती है, पर कोई कर अदा नहीं किया जाता। केवल सच्चे और वार्तविक किसानों के लिए ही मूल रूप से अभिप्रेत छूट के इस घोर और स्पष्ट दुरुपयोग को माफ नहीं किया जा सकता अथवा ऐसा होते रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि फार्महाउस को वार्तविक कृषि कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से होने वाली आय को कर जाल में लाया जाए, मैं कानून में उपयुक्त परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूं।

167. कर संग्रहण की प्रणाली को जहां तक संभव हो, प्रयोक्ता अनुकूल और सक्षम बनाने की मेरी अत्यधिक इच्छा रही है। करदाता को शीघ्र, सुविधापूर्वक और सम्मानपूर्वक कर अदा करने की स्थिति में होना चाहिए। इसे देखते हुए मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति तथा कंपनियां राष्ट्रीयकृत बैंक की ऐसी किसी शाखा में जहां उनका खाता है, अपना कर जमा कर सकें, कर-संग्रहण की मौजूदा उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार करने और उन्हें सशक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। यह सुविधा छ: में से एक योजना के अधीन शामिल सभी नगरों और शहरों में पहली अगस्त, 2000 से उपलब्ध होगी। प्रचालनात्मक कारणों से यह सुविधा प्रारंभ में केवल कम्प्यूटरीकृत शाखाओं में ही प्रदान की जाएगी परंतु इसका लगातार विस्तार किया जाएगा।

168. मैं कर वापसियों की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव करता हूं। जहां करदाताओं को उनके बैंकों को सूचित करते हुए वापसी का चैक भेजने की वर्तमान प्रथा जारी रहेगी, वहां कर विभाग भी निर्धारितियों के बैंक खाते में सीधे कर वापसी जारी करने की सुविधा प्रदान करेगा, यदि करदाता ऐसा चाहता हो। प्रचालनात्मक कारणों से यह सुविधा भी प्रारंभ में बैंकों की कम्प्यूटरीकृत शाखाओं से शुरू की जाएगी और बाद में बैंकों के कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ इसका निरंतर विस्तार किया जाएगा।

169. अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा विशेष सुविधा की अपेक्षा की आशा से हमारा आयकर अधिनियम छूटों का एक विशाल संकलन बन गया है। आय तो आय है, इस पर कर लगना ही चाहिए, कोई स्थाई छूट नहीं होनी चाहिए। इसको देखते हुए मैं रियायतों और छूटों की मौजूदा प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने की शुरुआत करना चाहता हूं। विभिन्न वस्तुओं की निर्यात आय पर इस समय आय के 50 से 100 प्रतिशत तक आयकर से छूट मिलती है। अतः मैंने पांच वर्षों की अवधि में इन रियायतों को धीरे धीरे समाप्त करने का निर्णय लिया है। मैं प्रारंभ में वित्तीय वर्ष 2000-2001 से इन रियायतों को 20 प्रतिशत तक वापस ले रहा हूं और उन्हें शून्य स्तर पर पहुंचने तक प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत के समान आधार पर कम करना जारी रखा जाएगा। निर्धारण वर्ष 2004-2005 की समाप्ति तक ये निर्यात आय पूर्णतः कर योग्य होंगी। इस 'सनसेट' (अंतिम) प्रावधान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के यौक्तिकीकरण और सरलीकरण के संदर्भ में

देखा जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि निर्यातकर्ता इसके पूर्णतः समापन तक न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट प्राप्त करते रहेंगे। इस यौक्तिकीकरण उपाय से अर्जित राजस्व से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण और मानव संसाधन में अन्य निवेशों को वित्तपोषित करने में सहायता मिलेगी।

170. युक्तिसंगतता लाने के मेरे उपायों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

- * शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल चलाने वाले न्यासों को छूट से इनकार नहीं किया जाएगा, भले ही उनके न्यासीगण उनसे चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त करते हों। ऐसे लाभों पर ही कर लगेगा।
- * न्यासों द्वारा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में किए गए निवेश एक निश्चित अवधि के लिये पात्र निवेश बने रहेंगे, भले ही वह विनिवेश के बाद सरकारी क्षेत्र की कंपनियां न रह गई हों।
- * म्युचुअल फंड और यूटीआई द्वारा वितरित लाभों पर कर और लाभांश कर के आस्थगित भुगतान के लिए ब्याज को प्रति माह 2 प्रतिशत से घटाकर प्रति माह 1.5 प्रतिशत किया जाना।
- * कर्मचारियों द्वारा प्राप्त भत्तों पर छूट पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बढ़ाई जाएगी।
- * व्यवसायविदों द्वारा खातों के अनिवार्य अनुरक्षण के लिए सकल प्राप्तियों की सीमा 60,000 रुपए से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए किया जाएगा।
- * अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा विभागीय अपीलों के निपटान की परामर्शी सीमा का कानून में प्रावधान किया जाएगा।

171. अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय इस बजट में प्रत्यक्ष करों पर किए गए विभिन्न प्रस्तावों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2000-2001 में अनुमानित राजस्व 72,105 करोड़ रुपये होगा जिसमें 5,080 करोड़ रुपये का निवल अतिरिक्त संसाधन जुटाने का घटक भी शामिल है।

172. अध्यक्ष महोदय, इन प्रस्तावों से मेरा अनुमान है कि केन्द्र की कुल कर राजस्व प्राप्तियां 1,46,209 करोड़ रुपए होंगी और राजकोषीय घाटा 1,11,275 करोड़ रुपए अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत होगा। मैं राजकोषीय घाटे में और कमी लाने के प्रयास कर सकता था, परन्तु राजस्व संग्रहण के काफी अधिक उच्च स्तर से इस समय चल रहे औद्योगिक सुधार को धक्का लग सकता था। अतः अत्यकाल में, मुझे राजकोषीय स्थिति के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता और विकास चक्र में समुत्थान के दौर को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के बीच सावधानीपूर्वक सन्तुलन बनाना था। मुझे आशा है कि यह महान सदन इस सन्तुलन का समर्थन करेगा जो मैंने इस बजट में बनाने का प्रयास किया है।

173. विकास अपने आप में एक साध्य नहीं है। यह रोजगार के अवसर बढ़ाने और हमारे लोगों, विशेषकर निर्धनतम लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाने का एक अतिमहत्वपूर्ण साधन है। ग्रामीण विकास में तेजी लाने, सड़क निर्माण, आवासीय सुविधाएं बढ़ाने, ज्ञान-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और मानव संसाधन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के हमारे सभी कार्यक्रमों के संयोजन में सतत व्यापक आधारयुक्त विकास से रोजगार के अवसरों में बहुन्न तेजी से बढ़ोत्तरी होगी। हमारे देश की गरीबी की समस्या का इससे बेहतर कोई समाधान नहीं हो सकता है।

174. महोदय, यह सहस्राब्दि भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व स्तर में आगमन के अग्रदूत के रूप में आयी है। दो वर्षों की अल्पावधि में हमने यह दिखा दिया है कि भारतीय प्रतिभा तथा भारतीय प्रयास किसी भी मायने में कम नहीं हैं। दो वर्षों की छोटी सी अवधि में हमने यह सुनिश्चित कर दिया है कि किसी भी उत्पाद अथवा सेवा के मामले में 'मेड इन इंडिया' एक सम्मान का प्रतीक बन गया है। दो वर्षों की इस अल्पावधि में हमने दुनिया के सामने यह तस्वीर पेश कर दी है कि भारत 21वीं शताब्दी में आर्थिक दृष्टि से एक महाशक्ति बनेगा। दुनिया की नजरें अब हमारी ओर हैं और हम बहुत कुछ करके दिखायेंगे।

175. अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह बजट इस सम्मानीय सदन को प्रस्तुत करता हूँ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2000

No. F. 15(8)-B(D)/99.—The following is published for general information :—

Sir,

I rise to present the first budget of this millennium.

2. This budget for 2000-2001 has some other firsts to its credit also. It is the first budget of the new Government which took office in October 1999 under the visionary leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee. It is also the first budget of the second half century of our Republic and the first budget of the new century. I hope it will add many more firsts to its credit as time goes by. I thank the Hon'ble Prime Minister for entrusting me with this historic responsibility which I stand here to discharge in all humility.

3. The year 1999-2000 has been a year of many challenges: the 50 day war in Kashmir, the super cyclone in Orissa, long months of political uncertainty before the general elections, a somewhat weak monsoon, a near tripling of world oil prices and the continued fragility in world economic recovery. Nevertheless, we have met these challenges resolutely, accomplished a great deal and the nation is stronger as a result.

4. The economy's performance is described in detail in the Economic Survey I laid before the House yesterday. Let me just touch a few highlights. A broad-based industrial recovery is under way. Despite lower growth of agriculture due to inclement weather, overall economic growth this year is expected to be nearly 6%. The infrastructure sector is performing much better. For the first time in 17 years the inflation rate has stayed below 4% for 42 consecutive weeks. Even more remarkable, the Consumer Price Index (Industrial Workers) in November 1999 showed zero increase

over the previous November. This is an enormous boon for the weakest sections of our society. Public food stocks are at record levels. Exports have achieved a remarkable turn around from negative growth last year to nearly 13% growth in dollar terms in April-December, 1999. Our software exports are also booming. Although surging international oil prices have increased our oil import bill by more than \$6 billion, our foreign exchange reserves have nevertheless attained new record levels. With the return of investor confidence our stock markets have also soared to new heights.

5. In my last two budgets I have addressed the accumulated shortcomings in our policies and freed our companies to compete globally. We have strengthened our agricultural sector, energised our financial markets and laid the foundations of an exciting new economy. With this, my third budget, I propose to put India on a sustained, equitable and job-creating growth path of 7 to 8% per year in order to banish the scourge of poverty from our land within a decade. The next 10 years will be India's decade of development. To achieve this objective our strategy must encompass the following elements:

- ◆ Strengthen the foundations of growth of our rural economy, especially agriculture and allied activities.
- ◆ Nurture the revolutionary potential of the new knowledge-based industries such as infotech, biotechnology and pharmaceuticals.
- ◆ Strengthen and modernise traditional industries such as textiles, leather, agro processing and the SSI sector.
- ◆ Mount a sustained assault on infrastructure bottlenecks in power, roads, ports, telecom, railways and airways.
- ◆ Accord the highest priority to human resource development through programmes and policies in education, health and other social services, with special emphasis on the poorest and weakest sections of society.
- ◆ Strengthen our role in the world economy through rapid growth of exports, higher foreign investment and prudent external debt management.
- ◆ Establish a credible framework of fiscal discipline, without which the other elements of our strategy can fail.

6. In all these areas we must pursue thorough-going economic reforms to unlock the creative energies of our people and thus reap the gains of productivity growth. But our reforms

must also be guided by compassion and justice. In his Address to Parliament in October 1999 the President has set out the broad outlines of our programme of second generation reforms. This budget carries forward the process of implementation.

Fiscal Management

7. Today, we must squarely confront and overcome the critical challenge posed by a weakening fiscal situation. A long history of high fiscal deficits has left us with a legacy of a huge public debt and an ever-growing bill of interest payments. This year we have incurred unanticipated expenditure on national defence, elections and the super cyclone in Orissa. The residual impact of the Fifth Pay Commission and the need for special fiscal assistance to the States have added to our burden. All this, combined with shortfalls in receipts from disinvestment and revenue, has raised our net borrowing requirements (our fiscal deficit) to over Rs.1,00,000 crore. This will add about Rs.10,000 crore to our interest bill next year. We must also find additional resources for Plan, Defence and for additional transfers to States under the interim award of the Eleventh Finance Commission. If we do not raise the resources and instead take recourse to even higher borrowing next year, then we will jeopardise our prospects for growth, reignite the flames of inflation, sow the seeds of another balance of payments crisis and place an unfair burden on the next generation.

8. We must put our fiscal house in order. This means hard decisions and sacrifices. At the same time we must preserve the intrinsic dynamism of our economy, which alone can deliver sustained growth with social justice. For this reason, despite the severe fiscal strain, the budget support to the plan is being increased by Rs.11,100 crore to a level of Rs.88,100 crore compared to Rs.77,000 crore in B.E. 1999-2000.

9. Similarly, there cannot be any compromise on Defence. Our forces have once again demonstrated in Operation Vijay that they are second to none in the world. Government is committed to enhance the quality of our defence preparedness and to modernise our forces. In this budget I have made a provision of Rs.58,587 crore for defence, which is nearly Rs.13,000 crore more than in B.E. for the current year. This represents the largest ever increase in the defence budget in any single year. More will be provided whenever needed. We shall not shrink from making any sacrifice to guard and protect every inch of our beloved motherland.

10. Over the years the composition of Central Government expenditure has become highly rigid and prone to large, pre-committed increases. More than half of the annual budget outlays

are transfer payments. Interest payments, Defence, Internal Security, Major Subsidies, Salaries, Allowances and Pensions and non-plan grants to States account for about 95% of non-plan expenditure and about 70% of total expenditure. To curb built-in expenditure growth and bring about structural changes in the composition of our expenditure, I am introducing the following initiatives.

- ◆ All ongoing schemes will be subjected to rigorous zero base budgeting scrutiny. I had announced this initiative last year and I am glad that this exercise has been completed in 8 Departments. As a result 69 schemes are to be discontinued or merged. This process will be completed in a timebound manner in the remaining Departments.
- ◆ The manpower requirements of Government departments will be reassessed by reviewing the norms for creation of posts.
- ◆ Fresh recruitment in Government departments and institutions will be limited to minimum essential needs.
- ◆ The scheme for redeployment of surplus staff will be made more effective and will provide facilities for retraining. A VRS scheme will also be introduced for staff in the surplus pool.
- ◆ All subsidies will be reviewed with a view to bringing in cost-based user charges wherever feasible.
- ◆ No new autonomous institutions will be created without approval of Cabinet. Budgetary support to autonomous institutions will be reviewed and they will be encouraged to maximise generation of internal resources.
- ◆ In order to align with the overall interest rate structure, the interest rate on General Provident Funds is being reduced by 1% to 11% from 1.4.2000.
- ◆ Excessive domestic borrowings to finance current expenditure has resulted in debt service payments approaching unsustainable levels. To reduce expenditure on this account, a portion of the disinvestment proceeds will be earmarked for retiring Government debt. An initial provision of Rs. 1,000 crore has been made in the budget for this purpose.

I will have something more to say on major subsidies a little later.

11. These measures are necessary and are only a beginning. We shall pursue resolutely the objective of downsizing Government

and prepare a roadmap for the purpose. For medium-term management of the fiscal deficit we also need the support of a strong institutional mechanism embodied in a Fiscal Responsibility Act. This had been suggested in the Agenda for Governance of the National Democratic Alliance. I have set up a committee to examine this issue and make suitable recommendations. I hope to bring the necessary legislative proposals to the House during the course of the year.

12. The challenge of fiscal management is not confined to the Central Government. The financial position of the State Governments has deteriorated sharply in the last few years. Revenue deficits have widened and borrowings are being increasingly used to meet revenue expenditure. Fiscal reform at the State level has acquired great urgency. While we have gone out of our way to help State Governments, the determination shown by some States to deal with these issues has also helped enormously. It will be my endeavour to take further collective measures in the next year for promoting fiscal reforms in the States. The final report of the Eleventh Finance Commission will provide valuable inputs for taking policy initiatives in this regard.

Agriculture and Rural Development

13. It is my firm belief that sustained and broad-based growth of agriculture is essential for alleviating poverty, generating incomes and employment, assuring food security and sustaining a buoyant domestic market for industry and services.

14. We must take all necessary measures to strengthen the rural economy. Credit flow to agriculture through institutional channels of commercial banks, cooperative banks and Regional Rural Banks is estimated at about Rs.41,800 crore this year. It is expected to increase by over 20 per cent to a level of Rs.51,500 crore in 2000-2001. In my last two budgets we have launched a wide array of initiatives to promote the flow of rural credit. In this budget I propose to strengthen the earlier programmes and launch further initiatives:

- ◆ The Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) managed by NABARD has emerged as a popular and effective scheme for financing rural infrastructure projects. Last year I had announced an enhanced allocation of Rs.3,500 crore from the banking sector for RIDF V and extended the repayment period of loans to 7 years. The scope of RIDF was also widened to allow lending to Gram Panchayats, Self Help Groups, NGOs and other eligible organisations for implementing village

level infrastructure projects. This year the corpus of RIDF VI will be increased to Rs.4,500 crore and the interest charged on this lending will be reduced by half a percent.

- ◆ Micro finance has emerged as an effective tool for alleviating poverty in many countries. In my last budget I had asked NABARD and SIDBI to cover 50,000 Self Help Groups to develop micro enterprises. NABARD by itself is likely to link 50,000 such Groups to banks during the current year. NABARD and SIDBI will cover an additional one lakh Groups during 2000-2001. To give a further boost to this programme a Micro Finance Development Fund will be created in NABARD with a start up contribution of Rs.100 crore from RBI, NABARD, banks and others. This Fund will provide start up funds to micro finance institutions and infrastructure support for training and systems management and data building. Special emphasis will be placed on promotion of micro enterprises in rural areas set up by vulnerable sections including women, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.
- ◆ The cooperative system is a crucial channel for credit in rural areas. However, over time, problems have developed, mainly because of excessive bureaucratization and the overlapping jurisdiction of State Governments and NABARD. Some State Governments have already taken legislative action to promote genuinely cooperative institutions. For rural credit, clear delineation of the supervisory role of RBI/NABARD on banking matters is also essential. To promote these two prerequisites for a more vibrant rural cooperative credit system I propose to establish a Fund in NABARD. The details will be worked out in the light of the forthcoming recommendations of the Kapoor Committee earlier constituted by Government. In the meantime, RBI is advising the banks to accord priority to the credit needs of those cooperatives which are entirely controlled by user-members and managed by them prudently.
- ◆ The programme of Kisan Credit Cards is progressing very well. Cooperative Banks, Regional Rural Banks and Commercial Banks together have so far issued more than 50 lakh cards and card-cum-pass books to the farmers. I am asking NABARD and Commercial Banks to redouble their promotional efforts so as to issue an additional 75 lakh Kisan Credit Cards by March 2001.

- ◆ Due to our efforts at recapitalizing RRBs, 158 RRBs are posting operating profits. Out of these, 48 RRBs have been able to wipe out their accumulated losses. In view of the importance of the RRBs in rural financing, we will continue with this programme of strengthening the RRBs.

15. The Planning Commission and the Ministry of Agriculture have worked out modalities to integrate 28 ongoing separate Centrally Sponsored Schemes of agricultural development into one comprehensive programme. This will weed out duplication, enhance the productivity of the support programme and accord greater flexibility to State Governments to develop and pursue activities on the basis of regional priorities. This is a major step forward towards the goals of convergence and decentralisation that I had outlined in my budget last year.

16. There is urgent need to review and coordinate our long-term strategy at the National and the State levels on the pattern of land use in the country, development of agriculture in relation to the agro-climatic conditions in the different regions and preservation of our forest resources. We need to adopt an integrated approach to a number of related subjects such as preservation and development of the forest wealth, optimum utilisation of the wasteland, watershed development, safeguarding bio-diversity etc. In view of the complexity of the issues involved, a National Commission on Land Use Policy comprising of experts in the relevant fields will be set up to examine the various aspects and make appropriate recommendations to Government.

17. Our Government stands fully committed to ensure that the fruits of economic reforms are shared by all sections of society, especially those living in rural areas and more particularly the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. Five elements of social and economic infrastructure are critical to the quality of life specially in rural areas: health, education, drinking water, housing and roads.

18. Even after 52 years of Independence the provision of basic services in rural areas remains very unsatisfactory. Forty per cent of our villages are without proper roads; 1.8 lakh villages do not have a primary school within 1 km; 4.5 lakh villages have drinking water problems; some estimates indicate a shortage of 140 lakh rural dwelling units; rural health infrastructure suffers from large deficiencies. These large gaps in basic services in rural areas are not acceptable and Government is committed to removing them rapidly.

19. Universalisation of elementary education is one of our key objectives. A new Department of Elementary Education and Literacy has already been created under the Ministry of Human Resources Development to give a new thrust and focus to these efforts. Some new initiatives include a scheme for universalisation of elementary education called "Sarva Shiksha Abhiyan" which would enable all children to enroll by 2003 and expansion of the District Primary Education Programme to cover the remaining districts in Uttar Pradesh, West Bengal, Orissa and Gujarat. On the literacy front the National Literacy Mission would be revamped so that the literacy rate can be raised to 75% by the year 2005. The plan allocation for elementary education has been increased from Rs.2,931 crore to Rs.3,729 crore next year. A new Department of Drinking Water Supply in the Ministry of Rural Development has been set up to intensify the efforts and accelerate the pace of coverage. Our objective is to provide drinking water facilities in all rural habitations in the next five years. It is proposed to cover around 60,000 habitations and 30,000 schools in the next year. The outlay of the Department is being enhanced to Rs.2,100 crore from Rs.1,807 crore this year. The Reproductive and Child Health programme will receive Rs.1,051 crore as against an allocation of Rs.695 crore in 1999-2000. For rural housing schemes a provision of Rs.1,710 crore has been made.

20. To impart greater momentum to these efforts I am announcing the launching of a new scheme, the "Pradhan Mantri Gramodaya Yojana" with the objective of undertaking time bound programmes to fulfill these critical needs of the rural people. I am providing a sum of Rs.5,000 crore separately for this Scheme in the budget. Out of this a sum of Rs.2,500 crore will be earmarked for launching a nationwide programme of constructing rural roads and improving rural connectivity. Under the Scheme, Central assistance will be provided to States for implementing specific projects in these sectors. The concerned Ministries in the Central Government will lay down the guidelines and monitor the implementation of these programmes. The erstwhile Basic Minimum Services Scheme will be merged with the new Scheme. Thus the overall provision in the budget for schemes concerning the five basic needs of the rural population is more than Rs.13,000 crore.

Rural Housing

21. "Housing for All" has been identified as a priority area in the Agenda for Governance. For the coming financial year, a goal of providing 25 lakh dwelling units in rural areas has been fixed. Schemes for meeting the needs of different sections of society have been prepared.

- (i) Under Indira Awas Yojana, it is proposed to provide more than 12 lakh houses for the people below poverty line. For this purpose, an amount of Rs. 1,501 crore is being provided in the budget.
- (ii) For families with an annual income of below Rs. 32,000 per annum, assistance will be provided for construction of 1 lakh houses under credit-cum-subsidy Scheme. An amount of Rs. 92 crore is being provided in the budget for this scheme.
- (iii) The National Housing Bank will provide refinance to banks and housing finance companies for construction of 1.5 lakh houses under Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme.
- (iv) To further improve the availability of housing finance in rural areas, Government have decided to provide equity support of Rs. 350 crore to HUDCO during the Ninth Plan period. Of this, Rs. 200 crore have already been released and it is proposed to release a further amount of Rs. 100 crore in the next year. With this enhanced equity support, HUDCO will be able to leverage these funds and raise further resources to facilitate and provide finance for the construction of about 9 lakh houses in the rural areas in the coming financial year.
- (v) The cooperative sector and voluntary agencies etc. will support the construction of another 1.5 lakh houses.

Social Security for the Poor

22. More than one third of our population still lives below the poverty line. There is an imperative need to extend some social security cover to the poorest sections of our society. I have decided to introduce a new scheme of group insurance, "Janashree Bima Yojana", under which beneficiaries will have insurance cover of Rs. 20,000 in case of natural death, Rs. 50,000 in case of accidental death or total permanent disability and Rs. 25,000 for partial permanent disability due to accident. Premia will be fixed on an actuarial basis. Below poverty line participants in this Scheme will pay only half the premium, with the remainder being contributed from earnings of LIC's existing Social Security Fund, suitably augmented by Government. On this basis, the monthly premium to be paid by the beneficiary is expected to be Rs. 10 or less. This scheme will lay a firm foundation for insurance cover to the poorest in our country.

Empowerment of Women

23. There is an urgent need for improving the access of

women to national resources and for ensuring their rightful place in the mainstream of economic development. Towards this objective, the Government will set up a Task Force under an eminent person to review all existing legislation and Government schemes pertaining to the role of women in the national economy. This Task Force will help us chalk out specific programmes for observing 2001 as "Women's Empowerment Year".

Population, Health and Environment

24. Government have recently announced a new National Population Policy a key objective of which is to bring down total fertility rates to replacement levels by 2010. To operationalise this objective, the plan allocation of the Department of Family Welfare has been increased from Rs.2,920 crore in B.E. 1999-2000 to Rs.3,520 crore next year.

25. Recognising the role of the Indian systems of medicine and homeopathy in our health care, the plan allocation for the concerned Department is being doubled. Emphasis will be placed on drug standardisation, quality control, modernising the colleges, drug testing laboratories and formulations. This will also help in boosting exports of herbal formulations.

26. We must preserve and nurture our forests and environment for future generations. Funds are being provided for regeneration of mangroves and creation of shelterbelts along the coastal line, bamboo regeneration and afforestation programme, encouragement of medicinal plants and eco-tourism. Preservation of the rural environment will raise the living standards of millions belonging to the weakest sections of our society.

Small Scale Industry

27. The SSI sector plays a vital role in industrial production, employment generation and exports. In the context of growing domestic and international competition, our strategy is to support this sector through promotional policies of credit and technology. For improving credit flow to SSI units, I propose the following:

- ◆ The requirement of providing collateral security is a major bottleneck to the flow of bank credit to very small units. RBI has recently issued instructions to dispense with the collateral requirement for loans up to Rs.1 lakh. The limit is being further increased for the tiny sector from Rs.1 lakh to Rs.5 lakh.
- ◆ The existing composite loan scheme of SIDBI and banks helps small borrowers by providing working capital and

term loans through a single window. To promote credit flow to small borrowers, the composite loan limit is being increased from Rs.5 lakh to Rs.10 lakh.

- ◆ I am asking the public sector banks to accelerate their programme of SSI branches to ensure that every district and SSI clusters within districts are served by at least one specialised SSI bank branch. Furthermore, to improve the quality of banking services, SSI branches are being asked to obtain ISO certification.
- ◆ Last year, I had announced that a credit guarantee scheme for SSI will be launched. I am glad to inform the House that a new Central Scheme for this purpose has been formulated and a provision for Rs.100 crore has been made in the budget. The Scheme will be implemented through SIDBI and will cover loans upto Rs.10 lakhs from the banking sector. The guaranteed loans will be securitised and will be tradeable in the secondary debt market.

28. SIDBI operates the National Equity Fund Scheme under which equity support is provided for projects up to Rs.15 lakh. To further help SSI entrepreneurs, this limit will be raised from Rs.15 lakh to 25 lakh.

29. SIDBI is presently administering the Technology Development Modernisation Fund Scheme for assisting technology development and modernisation of SSI units. The Scheme has certain concessional features including interest at prime lending rate for direct assistance and refinancing at 2% below prime rate for indirect finance. The operation of this scheme is being extended by another 3 years.

30. The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has been playing a very important role as an instrument to generate large scale employment in the rural areas with low per capita investment. Government will continue to encourage the Khadi and Village Industry Sector so that its products can become more competitive. For intensifying marketing efforts, the KVIC will introduce a common brand name for its products and also set up a professionally managed marketing company for domestic as well as export marketing.

Industry and Capital Market

31. In earlier millennia, India led the world on the basis of knowledge. Today history is repeating itself. Young Indian

entrepreneurs are at the forefront of the infotech revolution, whether in Silicon Valley, Bangalore or Hyderabad. They have shown us how ideas, knowledge, entrepreneurship and technology can combine to yield unprecedented growth of incomes, employment and wealth. Companies unknown 5 years ago have become world leaders. We must do everything possible to promote this flowering of knowledge-based enterprise and job creation.

32. A key ingredient for future success lies in Venture Capital Finance. After a thorough review, I am proposing a major liberalisation of the tax treatment for venture capital funds. I will describe the details later. To simplify the procedures, SEBI will be the single point nodal agency for registration and regulation of both domestic and overseas venture capital funds. Venture activity is not limited to dot.com companies! Ideas and entrepreneurship, which merit venture finance, can be found in all sectors of the economy. The tax laws and SEBI guidelines are being formulated accordingly. I should add that this liberalisation will give a strong boost for Non Resident Indians in Silicon Valley and elsewhere to invest some of their capital, knowledge and enterprise in ventures in their motherland.

33. In recent months stock markets have been buoyant all over the world, including India. Experience has taught us that there can be hard times as well. It is in such difficult times that institutions like investor protection funds of stock exchanges become really important. I will have something to say on this in part B of my speech.

34. Thanks to our prudent macro-economic management and calibrated approach to currency convertibility, we have successfully weathered the East Asian crisis of the past two years. But we must not confuse caution with timidity. We must encourage Indian firms and businesses to grow into strong, India-based multinationals. To promote this trend, it is necessary to accord our firms increasing flexibility to undertake capital account transactions, especially for acquisitions of businesses abroad. Last month, Government had announced a policy to allow Indian companies to raise funds for investments through issue of ADRs/ GDRs without prior Government approval. Up to 50% of these proceeds can be used by them to acquire companies in overseas market. We had also announced on 27th December, 1999, a liberalized mechanism for acquisition of software companies in the overseas market through stock swap options up to US\$100 million on an automatic basis. I plan to further liberalize this policy for acquisition of companies abroad to enable Indian corporates, in knowledge-based sectors to grow rapidly and lay

the foundation for Indian multinationals in areas where we have comparative economic advantage. For acquisition in other sectors too, I propose to increase the ceiling under the automatic route from existing US\$15 million to US\$50 million for Indian corporates and beyond this, through approval by the Committee on Overseas Investment.

35. Under existing policy on portfolio investment, Foreign Institutional Investors (FIIs) are permitted to invest in a company, upto an aggregate of 24% of equity shares, which can be increased to 30% subject to approval by the Board of Directors and a Special Resolution of the General Body of the Company. To give our best companies greater access to foreign portfolio investment, I am increasing this limit from 30% to 40%.

Science and Technology

36. The sustained growth of our knowledge-based industries will ultimately depend on the quality and extent of scientific and technological progress and training in our society. We must harness our potential in science and technology to realise the dream of modern India envisioned by the Prime Minister in his address to the Indian Science Congress last month. For taking up relevant technology vision projects and for increasing cooperation between our Universities and R&D institutions, I am making an additional provision of Rs.50 crore in the budget of the Technology Information Forecasting and Assessment Council under the Department of Science and Technology. I am also making a provision of Rs.50 crore in the budget of the Department of Scientific and Industrial Research for launching a New Millennium Indian Technology Leadership Initiative. It will focus on areas which fulfil national objectives and will be based on partnership between the Government and private sector.

37. To fully benefit from the new intellectual property rights regime, we need to encourage our scientists and R&D institutions to maximise their patenting efforts. Government have decided to allow Universities and Research Institutions to retain the revenue generated from intellectual property rights through publicly funded research and also share a part of the revenue with the inventor.

38. Modernisation of the Patent Office and the Trade Mark Register is long overdue. Government have sanctioned a modernisation project of Rs.75 crore for the Patent Office and we will strive to remove all impediments for early implementation of this project.

Banking and Finance

39. The recent East Asian crisis has underlined the critical

importance of undertaking reforms to strengthen the banking sector. In recent years, RBI has been prescribing prudential norms for banks broadly consistent with international practice. To meet the minimum capital adequacy norms set by RBI and to enable the banks to expand their operations, public sector banks will need more capital. With the Government budget under severe strain, such capital has to be raised from the public which will result in reduction in Government shareholding. To facilitate this process, Government have decided to accept the recommendations of the Narasimham Committee on Banking Sector Reforms for reducing the requirement of minimum shareholding by Government in nationalised banks to 33%. This will be done without changing the public sector character of banks and while ensuring that fresh issue of shares is widely held by the public. The Committee had also expressed the view that the Boards of the banks should have sufficient autonomy to take decisions on corporate strategy and all aspects of business management and be responsible to the stakeholders, that is, the shareholders, the customers, the employees and the public at large. In particular, the interests of the employees of the nationalised Banks will be fully safeguarded. It is proposed to bring about necessary changes in the legislative provisions to accord necessary flexibility and autonomy to the Boards of the banks.

40. As Honourable Members are aware, the Report of the Working Group on Restructuring Weak Public Sector Banks had suggested the constitution of a Financial Restructuring Authority (FRA). It has been decided to have a modified version of the FRA. Thus, in respect of any bank which is considered to be weak or potentially weak, the statutes governing public sector banks would be amended to provide for supersession of the Board of Directors on the basis of recommendations of the RBI and constitution of a FRA for such a bank, comprising experts and professionals. The amendments would also enable the FRA to exercise special powers including all the powers of the Board of the bank.

41. Government will not close down any public sector bank. As responsible owner of the banks, Government have decided to consider recapitalisation of the weak banks to achieve the prescribed capital adequacy norms, provided a viable restructuring programme acceptable to the Government as the owner and the RBI as the regulator is made available by the concerned banks.

42. The high level of Non-Performing Assets (NPAs) in our public sector banks is a cause for continued concern. Efficient and effective mechanisms for recovery of bank dues are critically important for reducing NPAs. I am happy to inform the House

that comprehensive amendments have been carried out to the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 by issue of Ordinance. Five more Debt Recovery Tribunals (DRT) and four more Debt Recovery Appellate Tribunals have been set up or are in advanced stage of being set up. I further propose to set up four more DRTs at Mumbai and one more DRT each at Calcutta, Delhi and Chennai to facilitate expeditious adjudication and recovery of dues of banks and financial institutions.

43. The growth of fresh NPAs can also be curbed through better institutional mechanisms for sharing of credit related information on borrowers and potential borrowers among banks and financial institutions. A Working Group constituted by RBI to examine modalities for setting up a Credit Information Bureau has recently submitted its report. Based on its recommendation a Credit Information Bureau will soon be established.

44. In the fast changing world of modern finance it has become necessary to accord greater operational flexibility to the RBI for conduct of monetary policy and regulation of the financial system. Accordingly, I intend to bring to Parliament proposals for amending the relevant legislation.

45. Similarly, to facilitate development of the Government debt market the legislative framework needs to be strengthened and modernised through a Government Securities Act, which I propose to bring to replace the old Public Debt Act, 1944.

46. The Industrial Investment Bank of India is the only Calcutta-based development financial institution. To enable it to improve its viability and profitability by diversifying and extending its business, Government will subscribe to the preference capital of the company.

47. NBFCs perform a significant role as financial intermediaries and in promoting growth of industry and services. Over the past 3 years RBI has taken a number of measures for strengthening the regulation of this sector with a view to ensuring that only financially sound and well run NBFCs are permitted to accept public deposits. I propose to bring a new bill which will strengthen the hands of depositors in situations of malafide or fraudulent actions of NBFCs.

Infrastructure

48. Infrastructure services remain a key bottleneck to rapid and sustained growth of our economy. We have made substantial progress in encouraging private infrastructure service providers and in establishing independent regulatory frameworks in most infrastructure sectors. We have also sought to give greater

operational and commercial autonomy to existing public entities in these sectors. We will be moving ahead with programmes for corporatisation of public sector service providers in the areas of telecommunications, ports and airports during the course of the coming year.

49. The Prime Minister has announced a major initiative for road development, the National Highways Development Project (NHDP). The cost of the project is estimated at around Rs.54,000 crore. In my earlier budgets, I had announced the levy of cess of one rupee per litre on petrol and diesel and a substantial part of this is expected to be available for funding the NHDP. To further augment resources, for commercially viable components of this project, I shall have something more to say in Part B of my speech.

50. The plan outlay for the Central PSUs in the power sector has been increased from Rs.7,626 crore to Rs.9,194 crore. Increased budgetary support has been provided for the Tehri Hydro and the Nathpa Jakhri Hydro projects so that both these projects can be commissioned by March 2002. For commissioning of high priority projects by SEBs/State generating companies, a provision of Rs.300 crore has also been made for subsidizing interest on loans from Power Finance Corporation..

51. In order to give a fillip to the reform process in the power sector and for undertaking investments on renovation and modernisation of old and inefficient plants and for strengthening the distribution system, a new scheme for providing assistance to State utilities will be introduced. Under this scheme, additional Central Plan assistance of Rs.1,000 crore will be provided to State and Union Territory Governments.

52. The State Electricity Boards have large overdues to the Central Sector Power and Coal utilities. A Scheme for securitisation of these dues with the support of Central Government has been finalized to assist the SEBs to clear these dues. Central Government support will be linked to reforms in the operation of SEBs.

53. Hon'ble members are aware that the Sethu Samudram Ship Canal Project has the potential of providing a shorter route between the East and West Coast Ports. I am glad to inform that Government have approved the undertaking of a detailed feasibility study and environmental impact assessment of the project at a total cost of Rs.4.8 crore. I have made necessary provision for this in the budget.

Disinvestment/Privatisation/Public Sector Restructuring

54. Government's policy towards the public sector is clear and unambiguous. Its main elements are :-

- ◆ Restructure and revive potentially viable PSUs;
- ◆ Close down PSUs which cannot be revived;
- ◆ Bring down Government equity in all non-strategic PSUs to 26% or lower, if necessary; and
- ◆ Fully protect the interests of workers.

55. In line with this policy during the last two years financial restructuring of 20 PSUs has been approved by Government. As a result, many PSUs have been able to restructure their operations, improve productivity and achieve a turn around in performance. Hon'ble members are aware that Government have recently approved a comprehensive package for restructuring of SAIL, one of our Navaratna PSUs.

56. There are many PSUs which are sick and not capable of being revived. The only remaining option is to close down these undertakings after providing an acceptable safety net for the employees and workers. Resources under the National Renewal Fund have not been sufficient to meet the cost of Voluntary Separation Scheme (VSS) for such PSUs. At the same time, these PSUs have assets, which if unbundled and realised, can be used for funding VSS. Government will put in place mechanisms to raise resources from the market against the security of these assets and use these funds to provide an adequate safety-net to workers and employees.

57. Government have recently established a new Department for Disinvestment to establish a systematic policy approach to disinvestment and privatisation and to give a fresh impetus to this programme, which will emphasize increasingly on strategic sales of identified PSUs. Government equity in all non-strategic PSUs will be reduced to 26% or less and the interests of the workers will be fully protected. The entire receipt from disinvestment and privatisation will be used for meeting expenditure in social sectors, restructuring of PSUs and retiring public debt.

The North-East Region

58. Government is committed to the speedy economic development of the North-Eastern States and Sikkim. Priority is being given for development of infrastructure, specially airports, railways, power and national highways so as to remove the sense of isolation perceived in many parts of the North-East. To provide

more facilities for vocational education, 50 more Industrial Training Institutes and 446 Computer Information Centres would be established in the North-Eastern States within the next two years.

59. For realizing the potential for agricultural and horticultural development in the North-East, schemes for minor irrigation and horticulture will be encouraged. A Technology Mission for horticultural development in the North-Eastern States will also be launched.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes

60. To promote literacy and to improve the education standards of persons belonging to Scheduled Castes, a new thrust will be given to the Post-Matric Scholarship Scheme. The budgetary provision for this Scheme is being increased from Rs.72 crore to Rs.130 crore. Emphasis under this Scheme will be on female literacy. Our Prime Minister has announced that it will be our national goal to liberate and rehabilitate around 6 lakh Scavengers in the country. A new strategy will be devised under which Scavengers will be organized into self-help cooperatives and provided assistance from the Government and the concerned Finance Development Corporations. To give a greater focus to the welfare of Scheduled Tribes, a new Ministry of Tribal Affairs has been set up. The plan allocation of Tribal welfare has been substantially stepped up from Rs.684 crore to Rs.810 crore.

Revised Estimates for 1999-2000

61. This has been a difficult year for the budget marked by expenditure over-runs and some deceleration in tax collection. The increase in budgeted expenditure has been 7% whereas shortfall in budgeted tax collection is estimated to be 4%. The non-plan expenditure has increased by Rs.17,461 crore (8.4% over budget estimate of Rs.2,06,882 crore) and the plan expenditure by Rs.2,395 crore (3.1% over budget estimate of Rs.77,000 crore). Major increases in non-plan expenditure are on account of pension payments (Rs.4,173 crore), interest payments (Rs.3,425 crore), Extended Ways and Means Advances to States (Rs.3,000 crore), Defence (Rs.2,810 crore), Interest subsidies (Rs.1,304 crore), food subsidy (Rs.1,000 crore), postal deficit (Rs.848 crore) and assistance to States from the National Calamity Relief Fund (Rs.1,064 crore). On the plan side, main increases are on account of National Highway Development (Rs.1,900 crore), State roads (Rs.1,000 crore), Railway safety (Rs.200 crore), special assistance to Jammu and Kashmir and enhanced assistance to States for externally aided projects. About Rs.500 crore are expected to be released for projects/schemes in the North Eastern

Region and Sikkim out of the savings from the budget of different Central Ministries.

62. Net tax revenues for the Centre are estimated at Rs.1,26,469 crore against Rs.1,32,365 crore budgeted, reflecting a shortfall of about Rs.5,900 crore. The shortfall is mainly due to lower customs revenue because of very low growth in the dollar value of non-oil imports and lower excise revenue resulting from low inflation in manufactured products for most of the year. Disinvestment receipts are expected to be Rs.2,600 crore against Rs.10,000 crore budgeted.

63. The fiscal deficit is thus likely to increase to 5.6% of GDP from the budget target of 4.0%.

Budget Estimates for 2000-2001

64. In the budget estimates for 2000-2001, the total expenditure is estimated at Rs.3,38,487 crore, of which Rs.88,100 crore is for plan and Rs.2,50,387 crore for non-plan.

Plan Expenditure

65. The budget support for Central, State and UT Plans has been placed at Rs.88,100 crore, marking an increase of Rs.8,705 crore over revised estimates 1999-2000. Gross budgetary support for the Central Plan is being enhanced from Rs.43,661 crore in the revised estimates 1999-2000 to Rs.51,276 crore. Total Central Plan outlay at Rs.1,17,334 crore will be more by Rs.21,024 crore from the last year's level of Rs.96,310 crore, a hefty 22% increase. The plan for 2000-2001 focuses on basic infrastructure with energy, transport and communications accounting for 60% of total Central Plan Outlay. The Outlay for Social Services marks an increase of 21.5% over 1999-2000 R.E.

66. Central Plan assistance to States and Union Territories in 2000-2001 is placed at Rs.36,824 crore as compared to Rs.35,735 crore in the revised estimates 1999-2000.

Non Plan Expenditure

67. Non-plan expenditure in 2000-2001 is estimated to be Rs.2,50,387 crore compared to Rs.2,24,343 crore in Revised estimates for 1999-2000, showing an increase of Rs.26,044 crore. The increase in non-plan expenditure is mainly in defence (Rs.10,083 crore), interest payments (Rs.9,841 crore) and in grants to States (Rs.9,392 crore). However, this increase is sought to be partially offset by reduction in outgo on account of food and fertiliser subsidies.

68. Major subsidies, on food and fertilizer, constitute a significant portion of our non-plan expenditure. The rate at which

these subsidy payments are growing is not sustainable. We need to target the subsidies to those who are poor and needy, whereas others should pay for what they consume. Indeed, we want to expand the access to subsidised food by Below Poverty Line (BPL) families so that they can meet their basic nutritional needs. Accordingly, from next year, we are doubling the allocation of foodgrains to BPL families, under the Targetted PDS, from 10 Kg. to 20 kg. This will result in an enormous gain in food security for our poorest families. The issue price of foodgrains of BPL families is being fixed at 50% of economic cost in line with the decision taken by Government in December, 1996. The net effect of these measures will be to improve the monetary food budget of BPL families and vastly enhance their food security. This achievement is possible only by simultaneously fixing the PDS issue price for APL families at the economic cost. In respect of sugar, no allocation will be made under PDS for income tax assessee. For others, keeping in view the increase in the levy price of sugar, the issue price under PDS is being fixed at Rs. 13 per kg. As a result of these measures I expect to keep the expenditure on food and sugar subsidy at Rs. 8,210 crore in 2000-2001.

69. In the case of Fertilizer Subsidy, Members are aware that our present Retention Price Scheme suffers from many shortcomings. Much of the subsidy goes to producers and not to farmers. To encourage greater efficiency of our fertilizer units, some rationalisation of the Retention Price Scheme, including capping of capital related charges, will be implemented from next year. The Ministry of Chemicals and Fertilizers will also bring out soon a road map for phasing out the Retention Price Scheme in the medium-term. Separately, to take into account the rising cost of inputs, the maximum retail price of Urea is being raised by 15%. The rate of concession in the case of decontrolled fertilizer is also being reduced. However, to moderate the impact on prices the MRP of DAP and MOP is being raised only by 7% and 15% respectively. I expect that, because of these changes and some rationalisation of Retention Price Scheme, the expenditure on fertilizer subsidy will be Rs. 12,651 crore in 2000-2001.

70. The Eleventh Finance Commission has since submitted its interim report for making provisional arrangements of tax devolution and grants to States for 2000-2001. Government have accepted the devolution formula and quantum of grants to States, as recommended by the Commission in its interim report. I have made provisions in the budget accordingly.

71. Sir, I now present my tax proposals. I take up indirect taxes first.

72. Hon'ble Members are aware that both the Centre and the States depend heavily on indirect taxes. While I did carry out a major restructuring of the excise rates last year, the process needs to be taken further. We need to overhaul the rate structure, rationalise and simplify the procedures to reduce the compliance cost for the tax payer. We must ensure that we concentrate on increasing production and absorbing new technologies rather than frittering away our energies on tax disputes.

73. Sir, my proposals in excise intend to establish a single rate Central Value Added Tax (CENVAT) at the Centre. I am convinced that nothing short of this can provide long term stability, remove uncertainties in the mind of industry, and eliminate disputes of classification. This will also encourage the States to implement their agreed programme for converting their sales taxes into VAT by 1.4.2001.

74. The House may recall that in my last budget, I had introduced three ad-valorem rates of basic excise duty, viz., 8%, 16% and 24%. I propose to converge these three ad-valorem rates to a single rate of 16% CENVAT.

75. The 8% excise rate is therefore being abolished and most of the items at this rate are being moved to 16%. However, certain items, essentially covering medicare and items of use by the

common man, are being exempted from the excise duty. These are:

Medical Items:

- ◆ Medicinal grade oxygen
- ◆ Medicinal grade hydrogen peroxide
- ◆ Anaesthetics
- ◆ Potassium iodate
- ◆ Medical and surgical gloves; and

Items of common use -

- ◆ Cutlery and knives
- ◆ House hold glassware, including glassware produced by mouth blown process
- ◆ Electric bulbs of MRP up to Rs.20 per bulb
- ◆ Clocks and watches of MRP up to Rs.500 per piece
- ◆ Tooth powder
- ◆ Sanitary towels, napkins for babies, etc, and
- ◆ Soap for distribution through PDS

76. I am including roasted chicory in the list of exempted items as coffee itself is free from excise duty.

77. I have also decided to exempt specified cold chain equipment, which had been provided a low rate of 8% in the last budget, from excise duty in the larger public interest.

78. Some items, on account of their exceptional nature and sensitivity to price increases, deserve special treatment, at least for the present. These are Kerosene, LPG, Laundry soap, Cotton yarn, including cotton sewing thread, and some other varieties of yarns and Diesel engines up to 10 HP. The rate structure for these is, therefore, being so designed that there is no increase in the incidence of excise from the current level of 8%, and thus there will be no price increase on this account.

79. I have not made any change in the list of items that are currently charged to 16% excise duty.

80. In addition to the 16% CENVAT rate, I propose to have three rates of special excise of 8%, 16% and 24%. Unlike the CENVAT rate, the special excise duties will not generally be modvatable, that is, users will not be able to avail of MODVAT credit of these duties.

81. For the items that are mainly in the nature of raw materials or intermediates, the 16% CENVAT rate is appropriate. I, therefore, propose to include items like plastic materials, films and sheets of plastic, tread rubber, cellular rubber, articles of rubber, nylon filament yarn, transmission and conveyor belts of textile materials, and sacks and bags made of synthetic textile materials in the list of 16% CENVAT, from the current level of 24%. I am also including tyres for OE supplies and parts of air conditioning and refrigerating machinery in the list of 16% CENVAT, without subjecting them to any special excise duty, since they are intermediate goods in the chain of production.

82. In addition, I am reducing the duty burden on a few other products that are also currently charged to 24% duty. These items are sterile contact lens solution, shikakai powder without additives, and cars for physically handicapped persons. I feel that these items should not be loaded with a duty burden of more than 16% CENVAT.

83. Ambulances purchased by registered hospitals are currently charged to a concessional rate of excise duty of 16%. I am extending the same treatment to ambulances purchased by Indian Red Cross Society.

84. The other items that are currently charged to 24% duty shall continue to bear the same incidence, comprising 16% CENVAT and 8% special excise duty.

85. In my new design of excise duty structure, the items that are now charged to a total duty of 30% would be subjected to a total duty of 32%, composed of 16% CENVAT and 16% special excise duty. This is only a marginal increase of 2%, which, I am sure, the consumers of these commodities can afford to bear.

86. Items presently charged to a total duty of 40% will now be composed of 16% CENVAT and 24% special excise duty. However, soft drink concentrate supplied to bottlers will be charged to CENVAT at 16% only, being modvatable.

87. Let me now take up the MODVAT scheme and the changes that I plan to bring about. MODVAT scheme shall now be known as CENVAT scheme.

88. Over the years, disputes between the department and assessees on the interpretation of MODVAT rules and procedures have plagued the system. I propose to put an end to this situation.

With effect from 1st April 2000, the plethora of existing rules will be replaced by a small set of simple and transparent rules, which, I am sure, shall reduce disputes to a minimum.

89. I also propose to expand and rationalize the scope of the MODVAT scheme. All inputs and all capital goods are now included in the eligible list of MODVAT scheme. The only exception will be High Speed Diesel Oil and Petrol. However, I propose that the availability of MODVAT credit on capital goods will be spread over a period of two years, with effect from 1st April 2000.

90. My proposals include full extension of MODVAT scheme to cigarettes for the first time, which should cheer the industry. However, the good news for the cigarette manufacturers ends here. I propose to enhance the rates of excise duty on all categories of cigarettes by 5 %.

91. At present, MODVAT credit of CVD paid on project imports is restricted to the extent of 75%. This has been an irritant. This credit shall now be available for 100% of the CVD. I have also decided to do away with the condition of installation as a pre-requisite for taking credit on capital goods.

92. Now I shall deal with some sector specific proposals. I take up steel first.

93. Mr. Speaker, Sir, an ad-valorem structure of taxation is largely free from distortions, equitable and automatically buoyant. For the present, I propose to restore ad-valorem excise duty structure on steel produced by re-rollers and also to steel produced by induction furnaces. These goods would be subjected to CENVAT of 16%, with MODVAT benefit, from 1st April 2000. I may add that capacity based tax applicable to re-rollers and induction furnaces has created more problems than it has solved.

94. Under the existing law, excise duty on goods sold from the depots is charged on the basis of depot price and not the factory gate price. I have received representations that this has caused distortion in the marketability and distribution of steel. Deliveries of steel by integrated steel plants, whether from the plant or stockyard, will henceforth be assessed to duty at the factory gate price.

95. Sir, now I turn to the textile industry.

96. I had introduced a compounded levy scheme for independent textile processors in December 1998. This has not

worked as well as expected and has led to leakages and revenue losses; still, I do not wish to disturb the scheme abruptly. However, to rectify the situation, I propose to raise the rates of compounded levy from the existing Rs.1.5 lakhs per chamber per month to Rs.2 lakhs per chamber per month and from Rs.2 lakhs per chamber per month to Rs.2.5 lakhs per chamber per month. My proposals also include some modifications in the scheme in order to plug the loopholes.

97. Units engaged in the texturising of duty paid polyester yarn would henceforth pay specific rate of excise duty. This should reduce the valuation disputes in respect of these units.

98. Small scale units enjoy duty free exemption on clearances up to Rs.50 lakhs a year. I am unable to raise this limit. However, with effect from 1st April 2000, I propose to rationalize the special schemes prevalent for cosmetics and toilet preparations, air-conditioning and refrigerating machinery and their parts, tread rubber and articles of plastics to fall in line with the general scheme of exemption for small scale units.

99. Sir, I now come to the next part of my proposals which relate to streamlining and simplification of the system. These are aimed at unshackling the excise procedures from the slavery of complexities and rigidities, and making them simple and user-friendly. I may add that like my rate-related proposals, these also go much beyond minor adjustments and mark a fundamental and even a dramatic departure from the current practices.

100. With effect from 1st July 2000, all statutory records in excise would be dispensed with. Excise department would rely upon the manufacturer's records. This completes the process initiated by me in my last budget in this regard.

101. From 1st April 2000, excise assessees would be allowed to pay the excise dues in fortnightly instalments. With this proposal I am putting an end to the age-old practice of day-to-day payment system of excise duties. For the small scale sector, the monthly payment scheme, that I had introduced last year, would continue.

102. Next, I want to make the valuation mechanism simple, user-friendly and along commercially acceptable lines. From 1st July, 2000, I propose to replace the existing section 4 of Central Excise Act which is based on the concept of "normal price" by a new section based on "transaction value" for assessment. This is a path breaking departure from the traditional approach.

103. The House is aware that several items are assessed to excise duty on the basis of Maximum Retail Price. This system is largely free from disputes and has been generally welcomed by the industry. I propose to extend MRP based assessment to about two dozen new items. I also propose to extend this scheme to more items during the course of the year.

104. I also propose to rationalize the rates of duties applicable to medicines and toilet preparations under the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act. The MRP-based assessment provisions are also being extended for assessment under this Act. These measures would considerably simplify the collection of excise duty by the States and improve their revenues from these duties. These changes will come into force from a notified date.

105. In addition to the above I am rationalizing the provisions relating to payment of interest and penalty on default. The details are contained in the Finance Bill.

106. This completes my package of restructuring and rationalisation on the excise side. Trade and Industry should now breathe easy.

107. I shall now deal with my proposals relating to customs duties.

108. I am conscious that in this area, I face serious constraints. We have to maintain a judicious balance between the need for providing adequate protection and growth impulses to the domestic industry and calibrating tariffs to international levels. We also need to carry the reform and rationalization process further.

109. Taking all factors into consideration, I propose to reduce the peak rate of basic customs duty from 40% to 35%, thereby reducing the total number of customs duty rates from 5 to 4, i.e. 35%, 25%, 15% and 5%.

110. The surcharge of 10%, which I am constrained to continue on revenue considerations, will also apply to the new peak rate of 35%. Crude oil and petroleum products, certain WTO bound items and gold and silver would continue to be exempt.

111. The House may recall that I had imposed a special additional duty (SAD) of customs in my budget proposals for 1998-99. This had made manufacturer-importers quite sad. But traders were glad because they were exempted. I am correcting

the discrimination by withdrawing this exemption. Now all importers would pay this duty. SAD would, however, not apply to petroleum products.

112. Consequent to our international trade treaty obligations, several hundred items will be placed on the free list for imports effective 1.4.2000. Most of these are consumer goods and a number of them are agricultural products. To accord adequate tariff protection for these items, they are being placed at the peak rate (35% plus surcharge), except for a few items like capital goods. A number of agricultural and horticultural products placed on the free list of import in earlier years are also being brought to the peak rate to ensure adequate protection to our farmers.

113. Furthermore, for a handful of sensitive agricultural products (wheat, rice, sugar and edible oils), in which our experience with supply management has underlined the importance of occasional tariff adjustments, I am making suitable enabling provisions to fix the statutory tariff rates at appropriately high levels. This will give the necessary flexibility for adjusting the applied rates.

114. Customs is not all about raising revenues. It is also a powerful tool for building our industrial capabilities and improving our international competitiveness. I propose to take several measures in this regard, picking up three sectors for special attention. These are integral parts of the "convergence revolution" which is fast becoming a reality.

115. First, and foremost, the Information Technology (IT) sector, which leads the current excitement. I propose to reduce the customs duty on several items for the IT sector. These include:

- ◆ Computers, from 20% to 15%;
- ◆ Mother boards, from 20% to 15%;
- ◆ Floppy diskettes, from 20% to 15%;
- ◆ Specified capital goods for manufacture of semi conductors and ICs, from 15% to 5%.
- ◆ Microprocessor for computers, from 5% to Nil;
- ◆ Memory storage devices, from 5% to Nil;
- ◆ CD ROMs, from 5% to Nil;
- ◆ Integrated circuits and microassemblies from 5% to Nil; and

- ◆ Data graphic display tubes for colour monitors for computers from 5% to Nil.

116. Telecommunications is equally important. To become an economic superpower we must get connected, domestically and globally. I, therefore, propose to reduce the basic customs duty on specified raw materials for manufacture of optical fibres from 15% to 5%. I also propose to reduce the duty on cellular phones from 25% to 5% to improve their availability through proper channels and to curb the menace of the grey market, and on their battery packs from 40% to 15%. I am extending the concessional rate of 5% basic duty applicable to specified telecom equipment to internet service providers also.

117. The third is the entertainment industry, which is also an area of great promise. To reduce the cost of cinematography for the film industry and provide access to the latest technology, I propose to reduce duty on cinematographic cameras, and other related equipment from 40% to 25%. I also propose to reduce the basic customs duty on colour positive films in jumbo rolls and colour negative films in rolls of certain sizes from 15% to 5%. They shall also be exempt from CVD.

118. I would like to cover one more sector in this context.

119. India can be a world leader in jewellery exports, as it is for gems. I propose to reduce the basic customs duty on platinum and non-industrial diamonds from 40% to 15% in order to encourage production of quality jewellery and to provide a fillip to jewellery exports.

120. To give effect to our agreements with the European Union and the United States, I propose to adjust the customs duties on fibres, yarns, textile fabrics and garments. As a result, several varieties of fabrics and garments would henceforth be subjected to the higher of ad-valorem or specific rates of duties prescribed for them.

121. As far as petroleum sector is concerned, the international prices of crude oil and petroleum products prevalent over some time now have been putting considerable strain on our refineries and distorting the oil pool account. This is accentuated by the fact that prices of petroleum products have not been fully decontrolled so far. I, therefore, propose to reduce the basic customs duty on crude oil from 20% to 15% and on petroleum products from 30% to 25%, except on kerosene for parallel

marketing, the basic duty on which is being raised to 35%, from 30%.

122. In several cases the bound rates are to be reduced as part of our international commitment. I do not wish to take the time of the House by going into details. But they do have some revenue implications.

123. Mr. Speaker Sir, last year, I had proposed the abolition of Finance Minister's discretionary power to grant ad hoc exemptions of customs and excise duties except for goods of strategic nature, or for charitable purposes. I am pleased to inform the House that this self-denying rule has helped the Government save about Rs.500 crore this year.

124. I shall now mention a few small, but significant, measures for procedural improvements and redressal of the problems of taxpayers. To curtail the so called "show cause notice Raj" in customs and central excise, I have decided that henceforth, show cause notices involving duty amount of more than Rs.1 crore would be issued only with the approval of the Chief Commissioner of Customs and Central Excise. Other show cause notices would require approval of the Commissioner of Customs and Central Excise.

125. It cannot be disputed that the tax due from a defaulter should flow to the exchequer at the earliest in public interest. At present, penalty equal to 100% of the duty evaded is payable, and this is mandatory, even if someone makes the payment immediately after the adjudication order is passed. With a view to encouraging payment of tax due, I have now proposed that if the amount of tax evaded is paid along with interest within 30 days of the communication of the order, a penalty equal to only 25% of the duty evaded would be payable. I hope this carrot will be found preferable to the stick, which is bound to follow if tax is not paid in time.

126. Service tax is emerging as an area of promise as well as problems. Many experts advise me that the best way to deal with this tax is to make it applicable to all services in one go. However, some others have suggested basic changes in the very structure of the service tax. I have decided not to make any changes for the present. I am setting up an Expert Group to go into all aspects of the matter, review the experience so far, and give me its considered advice.

127. My proposals on the excise side are estimated to result in revenue gain of Rs.3,252 crore in a year. On the customs side, my proposals are estimated to result in a revenue loss of Rs.1,428 crore.

128. Copies of the notifications issued to give effect to the changes in excise and customs duties shall be laid on the Table of the House in due course.

129. I now turn to my Direct Tax proposals.

130. Mr. Speaker, Sir, my edifice of Direct Tax proposals rests on four pillars of stability, economic growth, rationalisation and simplification.

131. Our existing rates of personal taxation at 10%, 20% and 30% are only three in number and quite moderate. Although the basic exemption limit is Rs.50,000, the real exemption limit goes much higher when the other exemptions and deductions are taken into account. For example, salaried persons start paying tax only on crossing Rs.75,000 per year because of the standard deduction. If the tax rebates and deductions available for savings are taken into account, the effective limit of exemption gets close to Rs.1 lakh. Thus I feel that the present rates of taxation as well as the exemption limit are reasonable. I, therefore, propose to maintain them at the same levels.

132. Although the 10% surcharge imposed last year was meant to be temporary, I am constrained to continue with it, in view of the heavy and unexpected expenditure burden, mainly on account of defence requirements and transfer to states mandated by the Finance Commission.

133. Having restrained myself from imposing any additional taxes during the course of the year when there was much talk of a Kargil tax, I now propose increasing the surcharge moderately from 10% to 15% on non-corporate tax payers having total taxable income above Rs.1,50,000 per year. This will slightly increase their marginal rate from 33% to 34.5%. I trust that these relatively better-off sections of society would bear this additional burden cheerfully.

134. Lest it is felt that I am being discriminatory in not increasing the surcharge on corporates, let me clarify that they would also get their opportunity to contribute to the national effort in other ways a little later.

135. Despite the financial constraints, I would like to propose some positive measures on personal taxation.

136. As an expression of our gratitude to the contribution made by senior citizens during their active years and taking into account the possible hardships that they face in the advanced years of their life, I propose to raise the tax rebate available to them from Rs.10,000 to Rs.15,000. At the marginal tax rate of 30%, this translates into an exemption of an additional Rs.15,000 from their gross income, or substitutes the need to save an additional Rs.25,000 to avail of a similar exemption under section 88.

137. I have always maintained that despite all challenges, my job as Finance Minister in making a budget is easier than that of an average house-wife struggling to balance the family budget. As a token of appreciation and recognition of women as productive contributors to the economy, I propose an additional rebate of Rs.5,000 for women tax-payers from their tax liability. This would be subject to the overall ceiling of Rs.15,000 if they also happen to be senior citizens.

138. With a view to acknowledging the services rendered by the members of defence forces and in token of our gratitude for their exceptional courage and valour, I had provided exemption from tax for the pension and family pension of gallantry award winners of these services. I now propose to extend similar benefits to gallantry award winners of para military forces and other forces engaged in national and civil defence.

139. I now turn to the role of taxation as a facilitator of economic growth. Knowledge-based industries are fast emerging as the front-runners of the Indian economy. To accelerate their growth, and encourage investment in them as mentioned in Part A of my speech, I propose to introduce a new regime for venture capital funds. The highlights of this would be:

- (i) No approval of Venture Capital Funds by tax authorities would be required.
- (ii) The principle of "pass through" would be applied in tax treatment of Venture Capital Funds, whose income would be free of tax, except when not distributed within the period that may be prescribed in the guidelines of SEBI.

62761/2000-9.

Income in the hands of its investors, which would otherwise be taxable, would also be kept tax free, and there would only be a one-time payment of tax by the Venture Capital Fund at the rate of 20%, when the Fund distributes its income to the investors. The same rate would apply to undistributed incomes also.

140. I hope these incentives will facilitate the coming together of *Saraswati* (i.e. knowledge) and *Laxmi* (i.e. wealth) to bless entrepreneurs and investors.

141. Various tax benefits are already available for the infrastructure sector. I propose to extend these benefits to two additional and essential sectors of urban infrastructure, viz. water treatment and solid waste management. I also propose to include investments in public companies providing long term finance for urban infrastructure as approved investments for charitable trusts. This will enable more investment in projects for development of urban infrastructure.

142. To provide a more focussed incentive for infrastructure development, I propose to delete the existing provisions 54EA and 54EB and replace them with a new provision, whereby tax exemption from capital gains would be available only if investment is made in bonds to be issued by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and the National Highways Authority of India (NHAI). These bonds will have a lock-in period of five years and their proceeds will be used for providing finance to the agricultural sector and for the National Highway Development Project (NHDP).

143. I propose to continue the thrust given to the housing sector last year and extend the benefits already available for two more years, i.e. for houses or projects which are completed by 31st March 2003. I hope this will sustain and accelerate house construction activity.

144. To supplement the package of incentives of this sector, I also propose that the 20% rebate of tax under section 88 of the Income-tax Act would now be available for repayment of housing loans up to Rs. 20,000 per year as against Rs. 10,000 earlier.

145. Presently, the exemption from tax on long-term capital gains is not available if the capital gain from transfer of capital assets is invested in a house, if one house is already owned. I am

removing this restriction. Even if they own one house, taxpayers can make an investment in a new house and claim exemption from capital gains tax on sale of capital assets.

146. Last year I had provided for 100% exemption on export profits to the entertainment industry. However, this benefit was limited to corporate entities only. I propose to extend the benefits available to corporates to non-corporate assessees as well with effect from Financial Year 1999-2000. This will remove the perceived discrimination to the non-corporate film makers, but I do hope that this industry will move towards corporatisation and modernization rapidly which is possible without in any way curbing individual creativity.

147. To address a long-standing demand of the entertainment industry and with a view to streamlining the procedures, I also propose to increase the limit of reporting of payments made by a film producer, during production of a film, to the tax authorities to Rs.50, 000 from the present level of Rs.25,000.

148. I hope these concessions combined with what I have already done on the indirect tax side, will reassure the entertainment industry that "Hum Saath Saath Hain".

149. Shipping provides the transportation sinews to our international trade, and has a strategic relevance also. To enable the Indian Shipping Industry, which is facing serious challenges, to generate resources for strengthening and modernising its fleet, I propose to allow deduction of their entire profits, against 50% as at present, if these are kept in a reserve to be used for purchase of new ships. This 100% deduction would be available for five years beginning from the next year.

150. Investment in human resources is an essential precursor for sustainable economic development. To enable meritorious students, especially those from not so affluent backgrounds, to avail of opportunities for higher education, I propose to increase the maximum amount of repayment of loan for higher education from Rs.25,000 to Rs.40,000 as an allowable deduction. This would translate into loan amounts exceeding Rs. 3 lakhs, which would help such students to defray the increasing cost of higher education, especially in management and professional courses.

151. Availability of vocational training can go a long way in mitigating the problem of unemployment. It can also bridge the paradoxical mismatch between wide spread unemployment on the

one hand and a shortage of properly trained manpower on the other. In order to remedy the situation I propose to allow 100% deduction of payments made for the establishment and running of institutions for vocational education and training by the private sector in rural areas and small towns.

152. Barring some significant but scattered achievements, we are not a major force in the international sports arena. Like many other activities, modern sports and athletics need money and infrastructure for their development. While some sports have access to abundant funding, most others suffer for want of adequate support. To rectify this situation, I propose that 100% deduction would be available for donations made by corporate entities to the Indian Olympic Association for the development of infrastructure and for the sponsorship of games and sports. I hope that with this concession, IOC would be better equipped to promote sports in the country.

153. Last year, my proposals on corporate restructuring were widely welcomed by Indian industry. However, there have been persistent demands to clarify and rationalise some of the provisions. I, therefore, propose to remove ambiguities in this regard by making suitable changes in the provisions of the Income-tax Act. I also propose that resulting companies as a consequence of splitting of statutory bodies like SEBs will enjoy the benefits of demerger if they fulfil the conditions notified by the Central Government.

154. Last year, I had dispensed with the condition of continuity of the same business for carry forward and set off of loss. I propose to liberalise the provisions relating to carry forward and set off of unabsorbed depreciation on the same lines. The condition of continuity of same business will be dispensed with and unabsorbed depreciation may be carried forward and set-off even if the same business is not continued.

155. To give greater restructuring flexibility and freedom to the corporates, including PSUs, I propose to make the conditions for tax exemption of voluntary retirement benefits of employees more liberal and to simplify the procedure for tax exemption of benefits given to employees of Public companies and Co-operative Societies. It will not be necessary any longer to obtain the approval of the tax authorities for their voluntary retirement schemes if these are formulated in accordance with the prescribed guidelines.

156. The various exemptions currently available while calculating Minimum Alternate Tax (MAT) and the credit system has undermined the efficacy of the existing provision and has also led to legal complications. To address these issues, I propose that the Minimum Alternate Tax be now levied at the revised rate of 7.5% of the "book profits" as determined under the Companies Act instead of the existing effective rate of 10.5%. However, this will now be uniformly applied – barring one exception that I will mention later. There will also be no credit for Minimum Alternate Tax paid. This should bring all zero tax companies within the tax-net, which is also the basic purpose of this tax. The new system has the virtue of a lowered rate of tax, a simple method of computation, and an equitable spread.

157. To promote industrialization in less developed areas, I propose to extend the tax holiday available for new units set up in industrially backward States and industrially backward Districts for another two years. Similarly, I also propose to extend the existing tax benefit for new Small Scale industrial units for another two years, i.e., till 31st March, 2002.

158. To strengthen our capital market, I propose to provide 100% exemption to the income of Investor Protection Funds of Stock Exchanges to give them incentives for setting up of such funds.

159. At present, no tax is payable in the hands of shareholders on the dividend income received from a domestic company, only the company pays additional income-tax at the rate of 10% on the amount of dividends distributed by them. The large gap in the tax treatment of dividend income and interest income has been widely criticized. To reduce this anomaly, I propose to increase the rate of tax on dividends distributed by domestic companies from 10% to 20%. I would clarify that dividend income in the hands of share holders will continue to remain tax free.

160. In a similar vein, to reduce the distortions arising out of the differing tax treatment for interest incomes from mutual funds and other instruments, like bank deposits and corporate deposits I propose to increase the rate of tax on income distributed by debt oriented Mutual Funds and UTI from 10% to 20%. However, I would like to clarify that the income distributed under the US-64 and other open-ended equity oriented schemes of UTI and Mutual Funds will continue to be exempt from this tax, as at present.

161. Currently, banks and financial institutions pay an interest tax of 2%, which adds to their cost. To remove this impediment to financial transactions, I propose to abolish this tax. This is a significant measure which will benefit the financial sector, and consequently the depositors and users of the products and services of the banks and financial institutions.

162. The life insurance sector is now opened up and would no longer remain a public sector monopoly. It is currently taxed at a special rate which is likely to need a revision in the altered scenario. I would like to undertake such revision on the basis of expert advice and in the light of international practice. I propose to constitute an Expert Committee for this purpose and I hope to bring necessary amendments based on its recommendations during the course of the year.

163. One of the major initiatives towards better tax compliance has been the introduction of the one-by-six scheme. This, along with other measures, has contributed substantially to increasing the number of tax-payers, which had languished at the level of just over a crore till 1996-1997, but has now crossed the two crore mark, with the biggest boost coming over the last two years. The momentum generated by this and other measures to widen the tax base needs to be sustained. I, therefore, propose to extend the one-by-six scheme from the existing 54 cities to an additional 79 cities in the country. With this, all the cities having a population of two lakh and more on the basis of the 1991 Census would stand covered.

164. In keeping with international practice, it is proposed to promote a common Business Identification Number to be used by different agencies and departments. In our context, the Permanent Account Number of income-tax would be that instrument. To begin with, the CBEC and DGFT will use PAN for their assessees, importers and exporters. I hope that in near future, the PAN card will replace the ration card as the primary identification document for a sizeable number of people.

165. With a view to intensifying the drive for PAN allotment, I propose to open special counters in all cities where the one-by-six scheme will be in operation (including 79 cities where the scheme is being extended) to issue PAN cards to the taxpayers within 30 days of their filing the application. This facility will become operational with effect from the 1st of July, 2000.

166. A large number of farmhouses have come up in the vicinity of metropolitan and big cities. Many of these generate commercial income from being hired out for residential accommodation and for holding functions and events. No tax is paid on this income, which is mis-declared as agricultural. This blatant and visible misuse of an exemption originally intended only for genuine farmers cannot be condoned or allowed to continue. I, therefore, propose to make suitable changes in the law to ensure that the income from farmhouse from anything other than genuine agricultural operations will be brought in the tax net.

167. It is my earnest desire to make the system of tax collection as user friendly and efficient as possible. The tax payer should be able to pay taxes with speed, convenience and dignity. With this in view, I propose to expand and revamp the presently available facilities of tax collection to provide that taxpayers would be able to pay their tax in any branch of nationalised banks where they maintain an account. This facility would be available in all towns and cities covered under the one-by-six scheme with effect from 1st August, 2000. For operational reasons, this facility would initially be offered in computerised branches only, but would be expanded continuously.

168. I also propose to further streamline the system of refunds. While the present practice of sending the refund cheques to the tax payers under advice to their banks would continue, the Tax Department would also offer the facility of issuing refunds directly on the bank accounts of assessees if the tax payers so desire. For operational reasons, this facility would also initially be started from computerised branches of banks, with continuous expansion as the banks get progressively computerised.

169. With almost every sector of the economy expecting a special treatment, our Income-tax Act has become a vast compilation of exemptions. Income is income and should be taxed. There should be no permanent exemptions. With this in view, I want to make a beginning towards rationalising the existing system of concessions and exemptions. Export earnings of various kinds presently enjoy exemptions from income-tax ranging from 50% to 100% of income. I have, therefore, decided to phase out these concessions over a period of five years. To begin with, I am withdrawing these concessions by 20% from the financial year 2000-2001, and by 20% each subsequent year till they reach a

zero level. I would add that exporters would continue to enjoy exemption from MAT till the full phase out. The revenues garnered from this rationalization measure will help to finance universalization of primary education and other investments in human resources.

170. My rationalisation measures also include the following:

- ◆ Trusts running educational institutions and hospitals will not be denied exemption even if their trustees avail medical and educational facilities from them. Such benefit alone will be taxed.
- ◆ Investments made by trusts in public sector companies will continue to be eligible investments for a certain period, even after they cease to be PSUs following disinvestment.
- ◆ Interest for delayed payment of dividend tax and tax on distributed profits by mutual funds and UTI will be reduced from 2% per month to 1.5% per month.
- ◆ Exemption of allowances received by employees will be raised in conformity with the recommendations of the Fifth Pay Commission.
- ◆ Limit of gross receipts for compulsory maintenance of books by professionals will be enhanced from Rs.60,000 to Rs.1,50,000.
- ◆ Advisory limit for disposal of departmental appeals by Appellate Tribunal will be provided for in law.

171. To sum up, Mr. Speaker, Sir, as a result of various proposals made in this budget on the direct taxes, the estimated revenue in 2000-2001 would be Rs.72,105 crore, including the component of additional resource mobilisation of Rs.5,080 crore.

172. Mr. Speaker, Sir, with these proposals I estimate total tax revenue receipts for the Centre at Rs.1,46,209 crore and the fiscal deficit at Rs.1,11,275 crore or 5.1% of GDP. I could have sought a deeper cut in the fiscal deficit, but a substantially higher level of revenue mobilization would have hurt the industrial recovery under way at present. Thus, in the short-run, I had to carefully balance the need for fiscal consolidation with the need to nurture the recovery phase of a growth cycle. I hope this august House will support the balance I have struck in this budget.

173. Growth is not just an end in itself. It is the critical vehicle for increasing employment and raising the living standards of our people, especially of the poorest. Sustained, broad-based growth, combined with all our programmes for accelerating rural development, building roads, promoting housing, boosting knowledge-based industries and enhancing the quality of human resources, will impart a strong impetus to employment expansion. There can be no better cure for the problem of poverty than this in our country.

174. Sir, the millennium has heralded the arrival of the Indian economy on the global stage. In two short years, we have shown that Indian talent and Indian effort is second to none. In two short years we have ensured that "made in India" is a compliment for any product or service. In two short years we have sent notice to the world that India will be an economic superpower in the 21st century. The world's eyes are now upon us, and we will deliver.

175. Mr. Speaker, Sir, with these words, I commend the budget to this august House.

